NOW NOIDA अपडेट

वॉल्यूम 1 | अंक 3 | March 2024

Title-Code: UPHIN51287

स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी शौर्य

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल

सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, भारत टेक्स-2024

अबकी बार 400 पार

मोदी हैं तो मुमकिन है

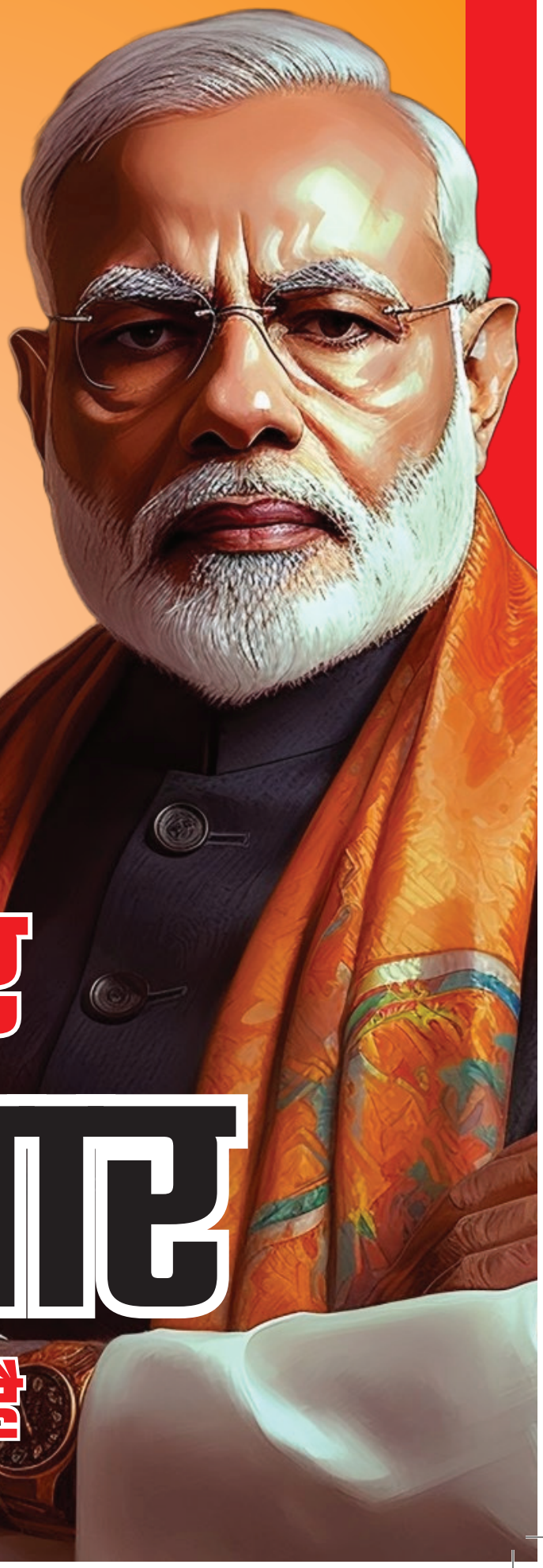

MBI

Direct From Factory

Deals in

- Men T-shirt
- Women T-shirt
- Boy T-Shirt
- Girls T-Shirt
- Bed-Protector
- Organic Swaddle
- Baby Gift

www.madebyindia.com | sales@madebyindia.com

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

संपादक मंडल

संपादक : संदीप कुमार ओझा

उप संपादक : पूजा मिश्रा

सहयोगी संपादक : निर्मल गौड़

नोएडा ब्यूरो चीफ : यूनुस आलम

वरिष्ठ संवाददाता : ओम प्रकाश सिंह

संवाददाता : साजिद अली

कला और सयंजोन : अनिरुद्ध शी, गुलशन कुमार

प्रबंध निदेशक : संदीप कुमार ओझा

निदेशक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 99 इकोटेक 3 उद्योग केंद्र 2 ग्रेटर नोएडा 201306

मुद्रक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD
प्लॉट नंबर-99, इकोटेक थर्ड, उद्योग केंद्र-2 ग्रेटर नोएडा-201306
दूरभाष- +91 120-4553364
infonownoida@gmail.com

एमबीआई डिजिटल प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सन्दीप कुमार ओझा द्वारा प्लाट नंबर-99, इकोटेक-थर्ड, उद्योग केंद्र-दो, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) से प्रकाशित व चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिग वर्क प्रा. लि. नोएडा, सी-40, सेक्टर-8 नोएडा से मुद्रित। संपादक सन्दीप कुमार ओझा (TITLE-CODE: UPHIN51287)

कंटेंट्स

वॉल्यूम 1 | अंक- 3 March 2024 मूल्य: ₹50

कवर स्टोरी

अबकी बार, 400 पार
मोदी हैं तो मुमकिन है

पृष्ठ - 16

किसान आंदोलन, MSP का बीज गणित	08
स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी शौर्य	12
मोदी का 100 DAYS प्लान, ऐसे बनेगा रिकॉर्ड	14
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 'महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएं'	20

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल	25
स्क्रैप की दुकान से अरबों तक का सफर	28
नफे सिंह राठी हत्याकांड, गहरी साजिश, विदेश तक तार	30
सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, भारत टेक्स-2024	32
CAA आ रहा है.	42

AAP विधा AAP विधायक दोषी, केजरीवाल की मुसीबत यक दोषी, केजरीवाल की मुसीबत	36
डॉक्टर का सुसाइड नोट	37
मोतियों की माला का कारोबार 20 देशों में बंपर डिमांड	38
जामनगर में अंबानी परिवार का जश्न	40

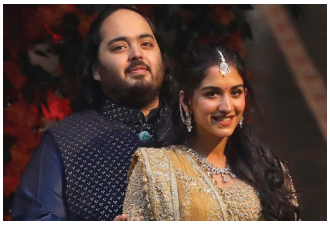

अंटार्कटिक में पहली बार मिला बर्ड फ्लू जानें क्या है ये बीमारी और कितनी खतरनाक	43
पाकिस्तान में 'शरीफ़' सरकार	46

बच्चे ही नहीं बड़ों में भी है मोबाइल की लत	03
कल्कि मंदिर का शिलान्यास, मोदी ने मिटा दी 'बाबर' की एक और निशानी	04
योगी का लिफ्ट ऐक्ट, बदमाश बिल्डर बचेंगे नहीं?	06

संपादकीय

मोदी की विदेश नीति की दुनिया कायल है। सुपरपावर अमेरिका हो या फिर उसका कट्टर दुश्मन रूस दोनों अगर कहीं एक मंच पर साथ दिखते हैं तो उसे सजाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। मोदी की कूटनीति के चर्चे G20 से ब्रिक्स जैसे शिखर सम्मेलन में होते ही रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक मिसाल ऐसी भी है जिसकी पूरी दुनिया में वाह वाही हुई। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की मान्यता पर मुहर लगी 8 भारतीयों की मौत के मुंह से वापसी के बाद। क़तर की जेल में बंद 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी उन्हें सुरक्षित वापस वतन ले आए इस पूरे प्रकरण को समझिए फिर मोदी के कद का अंदाज खुद ब खुद लग जाएगा। इन आठ भारतीय नागरिकों की गिरफ़्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहा था. क़तर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ़्तार किया लेकिन उनकी गिरफ़्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया था.क़तर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन भारतीयों को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई थी. लेकिन स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक़ गिरफ़्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियाँ इसराइल से साझा करने का आरोप है.

जेल से रिहा हुए ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टिंग सर्विसेज़ में काम करते थे.

ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में क़तर की नौसेना के लिए काम कर रही थी. इस प्रोग्राम का मक़सद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था.

पिछले साल क़तर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को पिछले साल ही मई के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इनमें ज़्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे.

जिन भारतीयों को गिरफ़्तार किया गया था उनमें कमांडर (रिटायर्ड) पूर्नेंदु तिवारी, कैप्टन (रिटायर्ड) नवतेज सिंह गिल, कमांडर (रिटायर्ड) बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन (रिटायर्ड) सौरभ वशिष्ठ, कमांडर (रिटायर्ड) सुग्नाकर पकाला, कमांडर (रिटायर्ड) अमित नागपाल, कमांडर (रिटायर्ड) संजीव गुप्ता, और सेलर रागेश शामिल थे.

केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार इन आठ पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए दबाव बन रहा था. कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी पार्टियां इन भारतीयों को जल्द भारत वापस लाने की मांग कर रहे थे.

ये रिहाई ऐसे समय हुई है जब पिछले सप्ताह ही भारत और क़तर के बीच एक अहम समझौता हुआ था. यह समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है.

भारत क़तर से साल 2048 तक लिक्विफ़ाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) ख़रीदेगा.

भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने क़तर की सरकारी कंपनी क़तर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है.इस समझौते के तहत क़तर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा. इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है. क़तर को जैसे भी मनाना था मोदी की टीम ने मनाया। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर मोदी ने भारतीयों की रक्षा की। एक दौर में कहा जाता था कि अमेरिका अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जाकर उन्हें बचाता है। यही बात आज भारत पर भी लागू है। नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।

संदीप कुमार ओझा
संपादक

बच्चे ही नहीं बड़ों में भी है मोबाइल की लत

मोबाइल की लत से विभिन्न बीमारियों होने की संभावनाएं

डॉ निखिल नायर
मनोचिकित्सक
शारदा हॉस्पिटल

बच्चे ही नही बड़ो में मोबाइल की लत लग जाती है। कई बार माता-पिता भी बिजी होने के कारण या बच्चे को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का लालच देते हैं। यही लालच देखते ही देखते उनमें एडिक्शन बन जाता है। जिससे बच्चे के विकास पर बुरी प्रभाव पड़ सकता है और बच्चा जिद्दी हो जाता है।शारदा अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ निखिल नायर बताते कई स्टडी ये बताती है कि जो बच्चे कम उम्र में स्क्रीन के संपर्क में आ रहे हैं, और जो बच्चे मोबाइल उपकरणों पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे व्यवहार संबंधी समस्याएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है, जो काफी चिंताजनक है। दिन में करीब 30 लोग ऐसे आते जिनमें 8 से 9 घंटे रोजाना फोन देखते है। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम होने पर आंख पर जोर,गर्दन और कंधे में दर्द,सिर दर्द,आंखो में सूखापन, गर्दन और कंधे में दर्द जैसी समस्या सामने आ सकती है. सबसे बड़ा असर आंखो को फोकस पर पड़ता है क्योंकि इसके बाद आंखे दूसरी चीजों पर बेहतर तरीके से फोकस नहीं कर पाती हैं।यदि आप सोच रहे हैं कि बच्चे की फोन की लत कैसे रोकें, तो हम आपको उसके कुछ तरीके बताते है।

डॉ निखिल नायर ने बताया कि स्मार्टफोन की लत का से बच्चे में अन्य गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा या रुचि में कमी आने लगती है, जिससे उसका कई चीजों को सीख पाने का मौका भी खत्म हो सकता है। अपने मोबाइल उपकरणों से चिपके रहने वाले बच्चों के पास अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने, बाहरी गतिविधियों में शामिल होने या सामाजिक समारोहों में मौज-मस्ती करने के लिए मुश्किल से ही समय होता है।

बच्चे को मोबाइल से बाहर निकालकर उनकी रुचि अन्य चीजों में पैदा कर सकते हैं। जैसे की पार्कों में जाएं, पैदल यात्रा करें, सैर पर जाएं और उन्हें बाकी दुनिया के साथ फिर से जुड़ने के लिए बढ़ावा दें।अकेलेपन से बचने के लिए लोग अपने स्मार्टफोन पर निर्भर हो जाते हैं।

बच्चे अकसर हर जगह फोन लेकर ही जाते है चाहे वे बेड रूम हो, डाइनिंग रूम हो। आप कुछ जगहों को ऐसा विकसित कर सकते है जहां को भी डिजिटल उपकरण ले जाने की इजाजत न हो। खाने के समय या बेड रूम में बच्चों को फोन न ले जाने दें।

बच्चे के फोन का लत को छुड़ाने के लिए आपको भी खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको यदि अपने बच्चे के फोन को सीमित करना है तो खुद के फोन चलाने का समय भी निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता।

कल्कि मंदिर का शिलान्यास, मोदी ने मिटा दी 'बाबर' की एक और निशानी

पूजा मिश्रा,
उपसंपादक़

19 फरवरी 2024 की तारीख पर एक इतिहास दर्ज हो गया। जब उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भगवान कल्कि मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मंदिर का निर्माण कल्कि पीठ करवा रहा है। जिसके पीठीधीश्वर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। जिन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे। कल्कि धाम के शिलान्यास पर प्रमोद कृष्णम पीएम की तारीफ के पुल बांधते रहे। वैसे भगवान कल्कि को विष्णु का आखिरी अवतार कहा जाता है। पुराणों में मान्यता है कि कलयुग के आखिर में, जब धरती पर पाप चरम पर होगा और धर्म पर संकट आएगा, तब भगवान अवतार लेंगे।

पूरी दुनिया में अनोखा मंदिर

कल्कि मंदिर विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि को समर्पित है। सनातन धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इस लिहाज से यह मंदिर दुनिया भर में अनोखा है क्योंकि जिस अवतार के लिए मंदिर बन रहा है अभी वह प्रकट ही नहीं हुए हैं।

अयोध्या के राम मंदिर वाला पत्थर लगेगा

इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, इन दसों गर्भगृहों में अलग-अलग दस अवतार स्थापित होंगे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जा रहा है जो अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर में इस्तेमाल हुआ है। इस मंदिर में भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। यह मंदिर 5 एकड़ में बनेगा। इसे बनने में 5 साल लगेंगे।

कल्कि भगवान का सफेद घोड़ा

बन रहे नवीन मंदिर के पास स्थित कल्कि पीठ में एक सफेद रंग के घोड़े की भी मूर्ति लगी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कल्कि अवतार को भगवान शिव देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा देंगे। इस

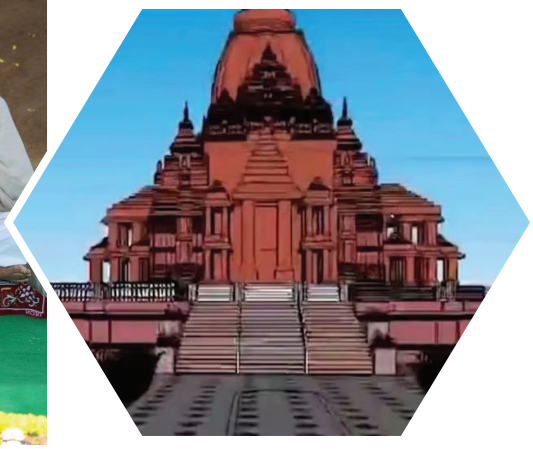

सफेद घोड़े की मूर्ति के तीन पैर जमीन पर हैं और चौथा हवा में उठा है। लोगों का कहना है कि यह पैर धीरे-धीरे नीचे झुक रहा है। जिस दिन यह पूरा झुक जाएगा समझा जाएगा कि कल्कि का अवतार हो चुका है।

500 साल पहले क्या हुआ था?

संभल में 500 साल पहले से भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल तीन मस्जिदों का निर्माण करवाया। जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है।

बाबर ने तुड़वाया था कल्कि मंदिर

इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की तारीख या याद के तौर पर वहां काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का नाम अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। तीसरी मस्जिद संभल में बनवाई।

संभल में जिस जगह शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, वहां कभी भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस-नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद की तामीर कराई। आज भी कल्कि मंदिर की दीवार और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आ जाते हैं।

अयोध्या के राम मंदिर से कनेक्शन

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्कि मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। अब कल्कि पीठ मंदिर निर्माण करवा रहा है। संभल में बन रहे कल्कि मंदिर और अयोध्या राम मंदिर के बीच कई समानताएं हैं। मसलन- कल्कि मंदिर का निर्माण भी उसी गुलाबी पत्थरों से होगा जिससे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है। भगवान कल्कि का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा। शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और 11 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का चबूतरा बनेगा।

भगवान कल्कि को जानिए

भगवान कल्कि, विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण अभी होना है. कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराएगा तब, भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतार लेंगे. कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे.

श्रीमद्भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख है और बताया गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे. बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का विष्णुयशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है-

शम्भल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः।
भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति॥

इसका मतलब यह है कि शम्भल गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े उदार हृदय वाले होंगे। इन्हीं ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि अवतार लेंगे।

मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदें बनवाईं. अयोध्या की बाबरी मस्जिद और पानीपत की काबुलीबाग के अलावा संभल में कल्कि मंदिर तोड़कर...

योगी का लिफ्ट ऐक्ट, बदमाश बिल्डर बचेंगे नहीं?

यूनुस आलम,
ब्यूरो चीफ़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में लिफ्ट एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लिफ्ट गिरने और बंद होने के कारण होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर और मेंटीनेंस एजेंसी को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। गाजियाबाद में अक्सर किसी न किसी सोसायटी में लिफ्ट गिरने फंसने व बंद होने की दुर्घटनाएं होती रहती है। कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ये कवायद है। क्योंकि बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जहां कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है, जिसमें लिफ्ट अचानक से चलते-चलते रूक जाती है, जो एक बड़े हादसे का कारण बनती है। यह देश के लगभग बड़े शहरों में मौजूद बड़ी इमारतों में देखने को मिलता है। लिफ्ट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए और अगर उसका उल्लंघन होता है तो क्या कार्रवाई होगी? इसकी जानकारी लिफ्ट एक्ट में मिलती है. यूपी में इस एक्ट की सख्त जरूरत थी जिसे योगी सरकार ने पूरा कर दिया है।

इन राज्यों में लागू है लिफ्ट ऐक्ट

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली एवं हिमांचल प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू है। इसी तर्ज पर UP में लिफ्ट एक्ट बनाने का निर्णय लिया गया। जानकारों का कहना है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग करते समय इनकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए उनके निर्माण, गुणवत्ता, आंतरिक सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

नोएडा में क्यों आएगी चुनौती?

नोएडा में इस एक्ट को लागू करना बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। जिले के करीब 1200 सोसाइटियों और हजारों वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों की करीब 50 हजार लिफ्टों को कानून के तहत क्रियाशील करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हालांकि इसके लिए एक्ट में समय दिया गया है। बावजूद इसके यह काम काफी मुश्किल भरा होगा। दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाईराइज इमारतों की संख्या एकाएक बढ़ गई। इन इमारतों

में लोगों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाए गए हैं। लेकिन इसके रखरखाव के बाबत कोई नियम नहीं बनाए गए। बिल्डर और अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन (एओए) अपनी सुविधा के मुताबिक इसका रखरखाव कर रहे हैं। मामले में बरती जा रही लापरवाही की वजह से इन इमारतों में रहने वाले लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। इससे निजात दिलाने के लिए लोगों ने लिफ्ट एक्ट की मांग सरकार से की थी।

लिफ्ट के पंजीकरण के लिए लगानी होगी दौड़

जिले के निजी एवं सार्वजनिक परिसरों में लिफ्ट लगाने से पहले राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। ऐसी सभी इमारतों के मालिकों को पंजीकरण के लिए दौड़ लगाना होगा। पंजीकरण के बाद इसे लगाने के लिए एक तय शुल्क के साथ विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेनी होगी। लिफ्ट क्रियाशीलता से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान मालिक इसकी वार्षिक तौर पर रखरखाव की रिपोर्ट देगा। यही नहीं इसका मासिक तौर पर रखरखाव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर भी रखेगा। एक वर्ष में कम से कम दो बार मॉकड्रिल कराएगा।

जानलेवा हादसे

29 अक्टूबर 2022 - सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सोसायटी में पांचवीं मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, बच्ची घायल हुई।

एक अगस्त 2022 - इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी में लिफ्ट खराब होने से आधे घंटे तक फंसे रहे बुजुर्ग दंपती।

21 मई 2023 - राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा कायमेरा सोसाइटी की लिफ्ट गिरने से बच्चा और बुजुर्ग महिला समेत परिवार के छह लोग घायल।

लोगों की सुरक्षा के लिए करनी होगी कड़ी मशक्कत

बिल्डिंग के मालिक को लाइट जाने के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों के बचाव के लिए ऑटेमेटिक रेस्क्यू सिस्टम लगाना होगा। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में लिफ्ट नजदीकी तल पर पहुंचे जाएगी। उसके दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वहीं इसके अलावा लिफ्ट में पर्याप्त रोशनी और अंदर फंसे लोगों से बाहर के लोगों की बातचीत की प्रणाली लगानी होगी। वहीं लिफ्ट में आपातकालीन घंटी होना अनिवार्य होगा। आपातकाल के दौरान कैसे बचाव किया जाए। इसकी जानकारी लिफ्ट के अंदर दी जाए। सार्वजनिक परिसरों में लगे हुए लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

संदीप ओझा,
संपादक

किसान आंदोलन, MSP का बीज गणित

किसानों का आंदोलन। दिल्ली कूच। हंगामा। उदप्रव। आंसू गैस के गोले। लाठियां। ट्रैक्टर। और बयानबाजी। दिल्ली की चौहद्दी पर घमासान। ये सुनकर देखकर कई दफे आप सोच में पड़ जाते हैं कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों का ये हाल क्यों है। क्यों वो सड़क पर आते हैं। सरकारों को ललकारते हैं। किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है। और ये MSP क्या है जिस पर महाभारत मचा है। MSP की गारंटी की मांग किसान क्यों कर रहे हैं। सरकार को ये गारंटी देने में दिक्कत क्या है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सबकुछ। पहले आप ये जानिए कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उनकी मांग क्या हैं?

MSP क्या है?

MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) किसानों के हित के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है। जिसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती

किसानों की मांग

किसानों की मांग है कि सरकार MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले. इसके लिए 700 रुपये की दिहाड़ी तय हो डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से MSP की कीमत तय हो किसान और खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ हो, उन्हें पेंशन दिया जाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर सख्त कानून बनाया जाए मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए संविधान की सूची 5 को अलग कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए

किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है। एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा। लेकिन किसानों का तर्क है उनकी खेती उद्योगपतियों के हाथों में जा सकती है।

है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाएं, तो किसान आश्वस्त रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम इस कीमत में जरूर खरीद लेगी। आमतौर पर MSP किसान की लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा होती है। अब ये समझना जरूरी है कि MSP सरकार की नीति है, कोई कानून नहीं। इसे सरकार घटा-बढ़ा सकती है। चाहे तो इसे बंद भी कर कर सकती है। किसानों को यही डर सताता है। आंदोलन की मुख्य वजह और गारंटी मांगने की वजह भी यही है।

कब होता है MSP का ऐलान?

सरकार साल में दो बार यानी एक बार ख़रीफ की फसल और एक बार रबी की फसल के दौरान MSP का ऐलान करती है. ख़रीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं, जिन्हें जून-जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। जबकि रबी की फसल सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर तक लगाई जाती है। रबी की फसलों में गेंहू, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसो और जौ प्रमुख रूप से शामिल हैं।

अभी कितने फसलों के लिए होता है MSP का ऐलान?

अभी तक सरकार 23 फसलों के लिए MSP का ऐलान करती है. इनमें 7 अनाज हैं - धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी और मक्का। 3 किस्म की दालें हैं - अरहर/तूर, चना, मूंग, उड़द और मसूर. 7 तिलहन हैं- मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तोरिया, तिल, सूरजमुखी बीज, कुसुम बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और रामतिल बीज। इसके अलावा 4 अन्य फसलों कच्चा कपास, कच्चा जूट, नारियल और गन्ने के लिए भी सरकार MSP तय करती है। राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है।

सरकार सभी फसलों पर MSP देती है, ये कैसे तय होता है?

फसलों का उचित दाम दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज (CACP) का गठन किया था। CACP ही MSP तय करता है। देश में पहली बार 1966-67 में MSP की दर से फसलों की खरीदी की गई थी।

MSP कैसे तय किया जाता है?

2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा गया। आयोग का मकसद किसानों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाकर उनका हल पता करना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थीं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट MSP को लेकर थी। आयोग ने बताया कि MSP क्या होना चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर UPA सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई। सरकार ने वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएगी। उन्हें उच्च किस्म के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कई बातें की गईं, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि वो एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि MSP को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से तय किया जाए।

स्वामीनाथन आयोग ने MSP तय करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था?

स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जो MSP होगा वह फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रुपए लगे। इसमें 50% यानी 500 रुपए जोड़ा जाए तो कुल MSP 1500 रुपये होगी। इसे C2+50% फॉर्मूला कहा जाता है। C2 मतलब कॉस्ट है। कॉस्ट यानी लागत तीन तरह के फॉर्मूले से तय होती है।

लागत तय करने के 3 फॉर्मूले कौन-कौन से हैं?

पहला फॉर्मूला A2- इसमें किसी ख़ास फसल के उत्पादन में किसान की लागत का आकलन किया जाता है. किसान की लागत आंकने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, लीज़ पर ली गई ज़मीन, मज़दूरी की लागत, मशीनरी और इंधन की कुल लागत देखी जाती है

दूसरा फॉर्मूला A2+FL: इसमें फसल पर किसान की लागत और उसके परिवार की मज़दूरी की क़ीमत भी तय की जाती है. अमूमन किसान खेतों में अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करते हैं. इस लागत में उनके परिवार की मेहत को भी शामिल किया जाता है.

किसानों से पांचवें दौर की वार्ता में सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, शांति बनाए रखना ज़रूरी : अर्जुन मुंडा

तीसरा फॉर्मूला C2: ये व्यापक लागत है, जिसमें A2+FL तो होता ही है. साथ ही इसमें अपनी ज़मीन के किराए की क़ीमत भी शामिल की जाती है. इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी पर ब्याज और लीज़ पर ली गई ज़मीन का किराया भी शामिल होता है.

स्वामीनाथन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि MSP देशभर में उत्पादन

की औसत लागत C2 से कम से कम 50% ज़्यादा दिया जाए यानी डेढ़ गुना दिया जाए. लेकिन सरकार MSP के लिए लागत C2 नहीं बल्कि A2+FL को मानती है और उसके अखिल भारतीय औसत से डेढ़ गुना देती है. आसान भाषा में फिर कहा जाए, तो स्वामीनाथन आयोग ने MSP तय करने के लिए C2 के डेढ़ गुना लागत की सिफ़ारिश की थी. लेकिन सरकार A2+FL का डेढ़ गुना के आधार पर MSP तय करती है.

MSP को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसने क्या काम किया?

नवंबर 2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी में अध्यक्ष सहित 29 सदस्य शामिल हैं. इनमें 18 सरकारी अधिकारी या सरकारी एजेंसियों और कॉलेजों से जुड़े एक्सपर्ट हैं. लेकिन अब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है.

स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले पर MSP देने से सरकार के रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा?

सरकार MSP वाली सभी 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद लेती है, तो सरकारी खजाने पर इसका गहरा प्रभाव होगा. ये बहुत ही भारी खर्च होगा. हालांकि, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सभी फसलों पर MSP गारंटी देने पर सरकार पर 10 लाख करोड़ का भार आ जाएगा. लेकिन इन अनुमानों का कोई आधार नहीं है.

फसलों पर MSP की कहानी 57 साल पुरानी MSP की कहानी 57 साल पुरानी है. 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी CACP बनाया, जो MSP को तय करता है. पहली बार 1966-67 में सरकार ने किसानों से MSP पर फसलें खरीदी थी. अभी सरकार 23 फसलों को MSP पर खरीदती है. इसमें 7 अनाज, 6 तिलहन, 5 दलहन और 4 अन्य फसलें शामिल हैं.

तो सारा सार ये है कि अगर सब कुछ तो दुरुस्त है, तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? असल में इस आंदोलन के पीछे पुरानी व्यवस्था को और मजबूती वाले भरोसे की मांग है। किसानों की मांग है कि सरकार जो MSP दे रही है, वो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दे। सरकार MSP पर गारंटी दे यानी उसको कानून बनाए। इससे सभी फसलों को MSP के दायरे में लाया जा सकेगा। MSP से कम कीमत पर कोई व्यापारी अनाज खरीदे, तो उस पर आपराधिक मुकदमा चले। सरकार के लिए ये मांग मानना इतना आसान नहीं। ऐसे में आंदोलन का दौर कब थमेगा इसे बता पाना मुश्किल है।

स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी शौर्य

पूजा मिश्रा,
उपसंपादक़

स्वामी प्रसाद मौर्य को न माया मिली न राम। न समाजवादी सियासत रास आई न ही कांग्रेस में कोई उम्मीद नजर आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग थलग पड़े स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नई पार्टी का झंडा बुलंद कर दिया है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किये गए हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संरक्षक और संस्थापक साहब सिंह धनखड़ ने मौर्य को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया। तो स्वामी प्रसाद शोषित समाज का कितना भला कर पाएंगे। क्या उनके सियासी अरमानों को नई पार्टी पूरा कर पाएगी। या फिर स्वामी प्रसाद का सारे ख्वाब अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। समझते हैं क्या है स्वामी की राजनैतिक हस्ती। जानते हैं उनका अतीत।

स्वामी प्रसाद मौर्य मूलरूप से प्रतापगढ़ जिले में चकवड़ के रहने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को चकवाड़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बदलू मौर्य के यहां हुआ। उनकी शादी शिव मौर्य से हुई है।मौर्य ने 1980 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत राष्ट्रीय लोकदल से की थी। लोकदल की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य बने और जून 1981 से 89 तक महामंत्री भी रहे। 1989 से 91 तक यूपी लोकदल के सचिव भी रहे। इसके बाद उन्होंने जनता दल का दामन पकड़ा और 1991 से 95 तक इस पार्टी के महासचिव पद पर रहे। दो जनवरी 1996 को बसपा की सदस्यता ली। प्रदेश महासचिव बने।

स्वामी प्रसाद मौर्य की बग़ावत पर तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 'बीएसपी को छोड़कर हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और ला स्नातक करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से ही 1996 में रायबरेली जिले के डलमउ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर पहली बार सदन पहुंचे। मई 2002 से अगस्त 2003 तक मंत्री रहे। अगस्त 2003 से बसपा के नेता प्रतिपक्ष रहे। 2007 से 2009 तक बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। इसी वर्ष उन्होंने कुशीनगर जिले की तरफ राजनीतिक कदम बढ़ाया और 2009 में कुशीनगर लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा।

कुंवर आरपीएन सिंह के चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद खाली हुई पडरौना विधानसभा सीट पर 2009 में हुए उप चुनाव पुन: बसपा के उम्मीदवार के रूप में मौर्य चुनाव लड़े और जीत मिली। 2012 में वे फिर एक बार विधानसभा चुनाव जीते। 2012 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट को रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से और बेटी संघमित्रा को अलीगंज से बीएसपी का टिकट मिला था लेकिन दोनों हार गए। साल 2016 के आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती से मतभेद हुआ जिसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय कहा था कि 'बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन चुका है, एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य की बग़ावत पर तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 'बीएसपी को छोड़कर हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना कुछ दिनों के अंदर ही हमारी पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, अर्थात इनको बीएसपी से निकालने वाली थी। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी कुशीनगर की पारंपरिक सीट पडरौना से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और 93649 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीएसपी के जावेद इकबाल को करीब चालीस हजार वोटों से हराया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट ने भी बीजेपी की टिकट पर ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ा था जिसमें सपा के मनोज कुमार पांडे ने उन्हें 1934 वोटों से हरा दिया था। स्वामी प्रसाद मोर्य भले ही दलित और शोषित समाज की राजनीति करते हैं लेकिन उनकी खुद की संपत्ति ठीक ठाक है।

कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं मौर्य?

मौर्य के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी शिवा मौर्य की कुल संपत्ति 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 50 हजार रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 65 हजार रुपये नकदी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 30 हजार रुपये की नीलम की अंगूठी

7 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी उनके पास एक रिवाल्वर और एक राइफल भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी शिवा मौर्य के पास एक फॉर्च्यूनर कार है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है. इसके अलावा, शिवा मौर्य के पास एक रिवाल्वर और रायफल है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास 7 लाख 50 हजार की ज्वेलरी है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और ला स्नातक करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम विज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने का हुनर आता है। लेकिन जिस राह पर अब वो चल पड़े हैं उसमें सत्ता की सीढ़ी का दूर दूर तक कहीं पता नहीं दिख रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद तब ही घटने लगा था जब उन्होंने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त की ही तो बात है ।

बीजेपी से क्यों हुआ मोहभंग?

जब यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा था, तब मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा 'मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया'। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी के ज़्यादातर नेता चुप थे। स्वामी प्रसाद गरज रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर तो बीजेपी और अगणों के खिलाफ आग उगलने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम चरित मानस से राम मंदिर तक पर विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। स्वामी प्रसाद के कोसने वाले बयानों से अखिलेश यादव के दल में भी कई नेताओं को नाराजगी झलकने लगी। आखिरकार स्वामी का मुखर विरोध होने लगा। समाजवादी पार्टी में भी स्वामी को सुनवाई जब बंद हो गई तब उन्होंने अलग रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का। देखना ये है कि दलित, शोषित समाज का स्वामी प्रसाद कितना शुभ कर पाते हैं ।

मोदी का 100 DAYS प्लान

ऐसे बनेगा रिकॉर्ड

दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का दो दिन 17 -18 फरवरी को अधिवेशन था। जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और लक्ष्य तक पहुंचने का रोडमैप दिखाया जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी कार्यकारणी की बैठक कई मायने में अनोखी रही। पूरा अधिवेशन राम मंदिर और मोदी पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह समापन के अवसर पर ऐतिहासिक भाषण दिया। जिसमें तीसरी बार मोदी सरकार के अभियान को सफल बनाने से लेकर विकसित भारत का विजन भी रखा। नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव में NDA के 400 पार का लक्ष्य रखा है। उन्हें चुनावी रैली में कहते सुना गया है कि बीजेपी 370 से अधिक सीटें हासिल करेगी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगा।

क्या है 100 दिन का प्लान?

पीएम मोदी ने कहा कि अगर एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करना है तो बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। मोदी ने हर नए वोटर से मिलना और उसे अपने साथ जोड़ना है का फॉर्मूला साझा किया।। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन में पार्टी कार्यकर्ता हर क्षेत्र और समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उनका भरोसा हासिल करेंगे। उन्होंने लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी ने प्रयास किया तो बीजेपी अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ देश की सेवा करने में सक्षम होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 50 लाख मतदाता फर्स्ट टाइम वोटिंग में हिस्सा लेंगे।बीजेपी के युवा मोर्चा ने नवमतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिन्हें देश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बनाए पांच हजार सेंटर के जरिए जोड़ा गया था. हर एक सेंटर पर एक हजार मतदाताओं को इकट्ठा किया गया था।

सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने अपना 'विश्लेषण और अंकगणित' जारी किया है कि भगवा पार्टी आगामी संसदीय चुनावों में 370 सीटों के सपने को कैसे साकार कर सकती है।

गढ़ सुरिक्षत रहे

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में 94 प्रतिशत था और उसने क्लीन स्वीप किया। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और झारखंड जैसे कई राज्यों में उसने कुल लोकसभा सीटों में से 94 प्रतिशत से अधिक जीतीं। इस तरह कुल 210 सीटों में से 198 सीटें उसकी झोली में आईं। इस बार भी पार्टी को वही 94 फीसदी स्ट्राइक रेट बरकरार रखना होगा, बल्कि इसे और बढ़ाना होगा।

राज्यों में NDA बेहतर करे

भाजपा ने उत्तरी क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त कर दिया लेकिन दक्षिणी राज्यों में उसका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी 80 में से 16 सीटें हार गई। इस बार, उसे इन अंतरों को पाटना होगा और देश के सबसे बड़े राज्य से और भी अधिक हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना होगा। इन 285 सीटों में से पार्टी ने 40 फीसदी के स्ट्राइक रेट से 114 सीटें हासिल कीं। पार्टी को इस बार स्ट्राइक रेट 57 फीसदी तक बढ़ाना होगा यानी 285 में से 161 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी।

शिवसेना और एनसीपी के साथ समीकरण

महाराष्ट्र भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बना हुआ है। उसने 2019 के चुनावों में 23 सीटें जीतीं, जबकि उसकी प्रमुख सहयोगी शिवसेना को 18 सीटें मिलीं। दोनों ने 48 में से 41 सीटों पर कब्जा किया, जिसके परिणामस्वरूप स्ट्राइक रेट 85 प्रतिशत रहा। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद भाजपा को न केवल अपनी 23 सीटें बरकरार रखने की उम्मीद होगी, बल्कि 18 सीटों पर जीत की भी उम्मीद होगी।

1984 में कांग्रेस जीती थी 415 सीट

राजीव गांधी की अगुआई में कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में 533 में से 415 सीटें जीती थी. पार्टी का वोट शेयर भी 49.01 फीसदी था. भारत के इतिहास में यह अब तक की सर्वाधिक बहुमत वाली सरकार रही है. हालांकि, बंपर जीत हासिल करने के बाद अगले चुनाव में कांग्रेस विपक्ष में रही और सिर्फ एक बार ही (1991 में) अपने दम पर सरकार बना पाई है. 2004 और 2009 में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा थी. इसके बाद से पार्टी विपक्ष में है।

संदीप ओझा,
संपादक

अबकी बार,

400 पार

मोदी हैं तो मुमकिन है

मोदी को महारथ है। दिलों में बसने में। जनमानस से जुड़ने में, एक झटके में किसी भी मुद्दे को लहर में बदलने में उनका कोई सानी नहीं। चुनाव दर चुनाव मोदी ये साबित करते जा रहें हैं कि मौजूदा दौर में चुनावी राजनीत में वो अजेय हैं। लेकिन 24 के रण में नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन तक पहुंचना आसान नहीं। ये लक्ष्य है 400 पार का। पीएम मोदी ने बीजेपी की 370 सीट और NDA को 400 पार का टारगेट सेट किया है। मोदी का ये मिशन कैसे तय होगा। विस्तार से जानते हैं कैसे मुमकिन होगी इतनी बड़ी जी।

पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में NDA 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगा। मोदी ने कहा 'मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा. देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे अपार भरोसा है"

पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, 'अबकी बार 400 पार'. 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है।

सवाल यह उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा? पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। ऐसे में हम बतातें है कि आखिर एनडीए के 400 पार का गुणा-गणित क्या है, बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को किन राज्यों में फायदा तो कहां सियासी नुकसान की संभावना है?

उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटों की बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है.

महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा. 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है बल्कि इजाफा करने की है।

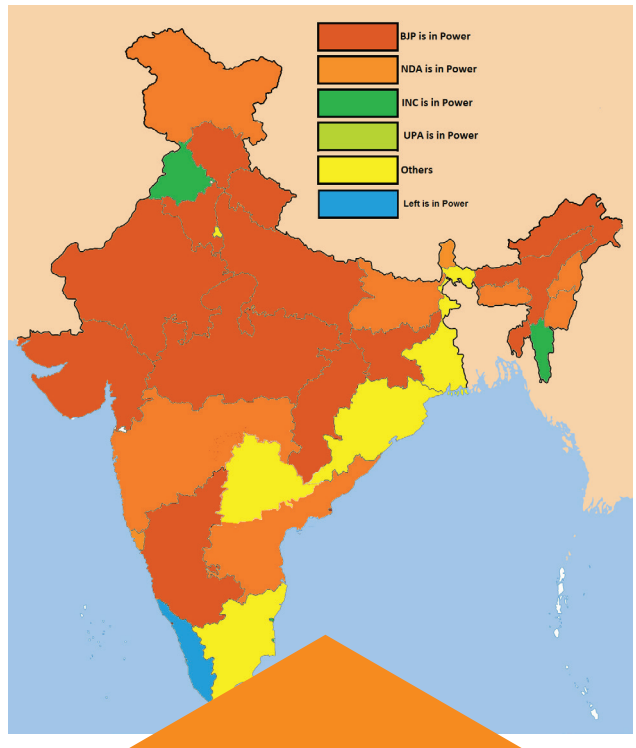

बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है

400 पार का गणित

पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह करने के बाद अब 2024 उतरने जा रही है । कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्य में बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानि 245 सीटें पर जीतना आसान नहीं, लेकिन 2019 की तुलना में उसकी सीटें बढ़ सकती है।

400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से हैं। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ ले लिया है, जिसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीट में से 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 16 सीटों पर हार मिली थी। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग-अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2014 में इसी तरह की स्थिति थी, तब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थीं और 2 सीटें उसके सहयोगी को मिली थीं। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी है और अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है। इस तरह बीजेपी को यूपी से 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है।

इन राज्यों से उम्मीद?

छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, उसके चलते माना जा रहा है कि क्लीन स्वीप कर सकती है। ऐसे में बीजेपी को दो सीटों का इजाफा हो सकता है। पंजाब में दो सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूबे के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ मिलाया है, उससे लगता है कि पार्टी की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं. बीजेपी पहली बार पंजाब में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी ने 4 से पांच सीटें जीतने का प्लान बनाया है।

झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी 11 सीट पर काबिज है और 2024 में उसे बढ़ाने की कवायद में है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी सीटें 11 से बढ़ाकर 12 और 13 तक ले जा सकती है। महाराष्ट्र में सियासी बदलाव के बाद बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी (अजित पवार गुट) और शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीटें शेयर करनी होंगी, जिसमें पिछली बार से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में दो लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास एक सीट है, जो बढ़कर दो हो सकती हैं।

दक्षिण के दुर्ग में सेंध

एनडीए के 400 पार के आंकड़ा पार करने के लिए दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज करनी होगी । इन राज्यों में कुल 104 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास सिर्फ चार सीट हैं, जो तेलंगाना में मिली थीं। कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन करके राज्य की 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने एक बार फिर टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा

है। आंध्र प्रदेश में खाता खोलने की चुनौती है, तो तेलंगाना में बीजेपी को अपनी 4 सीट को बढ़ाकर 6 से 8 करनी होंगी।

केरल और तमिलनाडु में बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, जिसका नाम तमिझगा वेत्री कड़गम रखा है। बीजेपी की नजर दक्षिण के फिल्मी स्टार पर है, जिसके जरिए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की है। केरल में पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक्टर-राजनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शिरकत की थी और वर-वधू को आशीर्वाद दिया था. सुरेश गोपी को बीजेपी केरल से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस तरह बीजेपी दक्षिण के राज्यों में 8-8 और 10-10 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी।

बीजेपी की नजर दक्षिण के फिल्मी स्टार पर है, जिसके जरिए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की है

पूर्वोत्तर में कमल

बीजेपी के आगे चुनौती पूर्वोत्तर के साथ-साथ ओडिशा और बंगाल में भी अपने चुनावी नतीजों को बरकरार रखने की नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की है। बीजेपी 2019 में ओडिशा की 21 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश उसे बढ़ाकर 10 से 12 तक ले जाने की है। पीएम मोदी ने इस दिशा में अपने दौरे भी ओडिशा से शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी।

पूर्वोत्तर राज्य में भी बीजेपी के लिए विस्तार की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नवीन पटनायक और ममता बनर्जी की छवि के सामने ज्यादा उम्मीद करना आसान नहीं है। 400 पार के सपने पूरे करने के लिए बीजेपी को बंगाल और ओडिशा में अपनी सीटों को इजाफा करना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 11 पर काबिज है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के चलते सिर्फ असम में ही बढ़ने की उसकी उम्मीद है।

असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, जहां तीन से चार सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की कोशिश असम में अपनी 9 सीटों को बढ़ाकर 12 तक ले जाना होगा। अरुणाचल से लेकर मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर की सभी 25 सीटों को बीजेपी गठबंधन अपने पास रखने की जुगत में है।

वोट का इजाफा, सीटों में मुनाफा

बीजेपी की कोशिश 2024 के चुनाव में अपने वोट फीसदी को बढ़ाने की है. 2019 में बीजेपी को 37 फीसदी वोट मिले थे, जिसके चलते 303 सीटें उसे मिली थीं। बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने वोट परसेंट को बढ़ाकर 47 फीसदी तक ले जाने में सफल हो जाती है तो फिर उसका आंकड़ा 370 सीट तक पहुंच सकता और एनडीए 400 पार हो सकती है, लेकिन उसके लिए उत्तर भारत में अपनी सीटों को बरकरार रखते हुए दक्षिण के राज्यों में अपनी सीटों का इजाफा करना होगा। दक्षिण भारत की 131 सीटों में से बीजेपी अगर 60 से 70 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तभी जाकर पीएम मोदी के 400 पार का सपना साकार हो सकता है?

इन सबसे ऊपर अगर कोई गणित है तो वो है नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड। जिसकी टक्कर में कोई नहीं। मोदी ही चुनाव के मुद्दे तय करते हैं। मोदी ही चुनाव का रुख बदलते हैं। मोदी ही जीत और हार के अंतर पर असर डालते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने का अपना मैनेजमेंट बनाते हैं उसी रोडमैप पर चलकर इतिहास बनाते हैं।

डॉ. प्रियंका सिंह
एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024

'महिलाओं में निवेश करें. प्रगति में तेजी लाएं'

"दुनिया की महिलाओं की प्रगति" संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा एक ऐसी दुनिया की दिशा में की गई प्रगति की आवधिक जांच है जहां महिलाएं, लड़कियां और लिंग-विविध लोग असमानता, गरीबी और हिंसा से मुक्त रहते हैं। उत्तेजक और व्यावहारिक, यह श्रृंखला बहु-वर्षीय शोध, गहन विश्लेषण और डेटा निष्कर्षों का उत्पाद है जो अग्रणी संगठनों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों की विशेषज्ञता पर आधारित। सामाजिक विकास के लिए पुरुषों के योगदान के साथ ही महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि आज ये कहने में भी हमे जरा भी संकोच नहीं होनी चाहिए कि देश के विकास के लिए भी महिलाओं का योगदान उतना ही जरूरी है, जितना की पुरुषों का। वैसे तो हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन से मंजूरी मिलने के बाद हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक खास दिन है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण, योगदान और सम्मान के लिए समर्पित करते हैं।वैसे तो सिर्फ एक ही दिन नहीं, उनके योगदान के लिए हर रोज सराहना की जानी चाहिए। लेकिन एक खास दिन निर्धारित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व महिला दिवस के रूप में मनाने का, जो कि 8 मार्च हैं। ऐसा माना जाता है कि महिला दिवस (Women's Day) की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क में हुई जब एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें लगभग 15000 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। उनकी मांग थी समानता का अधिकार फिर चाहे वह काम में हो, वेतन में हो या मतदान में। एक साल बाद इस दिन को अमेरिका में राष्ट्रीय महिला दिवस (National Women's Day) के रूप में मनाया जाने लगा जिसे अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी

ने एक्टिविस्ट थेरेसा मल्कील (Theresa Malkiel) के सुझाव पर आयोजित किया गया था।

अमेरिका के इस प्रसंग से प्रेरित हो कर साल 1910 में क्लारा ज़ेटकिन (Clara Zetkin), केट डंकर (Käte Duncker), पाउला थिएड (Paula Thiede) और अन्य जर्मन प्रतिनिधियों ने "महिला दिवस" की स्थापना का प्रस्ताव रखा। जिसमे 17 देशों के 100 प्रतिनिधियों ने महिलाओं के मताधिकार सहित अन्य क्षेत्रों में समान अधिकारों पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।अगले वर्ष, 19 मार्च 1911 को, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसमे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में दस लाख से अधिक लोगों ने अलग-अलग जगह प्रदर्शन किये। इस में महिलाओं के मतदान के अधिकार, सार्वजनिक पद पर आसीन होने की मांग और रोजगार में लैंगिक भेदभाव का विरोध किया।

उस समय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (Antrashtriy Mahila Divas) मनाने की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी, हालांकि यह आम तौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाया जाता था। अमेरिकियों ने फरवरी में आखिरी रविवार को "राष्ट्रीय महिला दिवस (National Women's Day)" मनाना जारी रखा, जबकि रूस ने 1913 में पहली बार फरवरी में आखिरी शनिवार को महिला दिवस मनाया।

इसके बाद 1917 में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने खाना और शांति (ब्रेड एंड पीस – Bread & Peace) के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध इतना संगठित और प्रबल था कि था कि तत्कालीन सम्राट श्री ज़ार निकोलस (Tsar Nicholas II) को अपना पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भी मिला। रूसी महिलाओं ने जिस दिन इस विरोध प्रदर्शन कि शुरुआत की थी, वह दिन 28 फरवरी (जूलियन कैलेंडर पर आधारित) था और जॉर्जियाई कैलेंडर (Gregorian Calendar) में यह दिन 8 मार्च था, तब ही से 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (Antrashtriy Mahila Divas) मनाया जाने लगा।

इतने लम्बे संघर्ष के बाद भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (Antrashtriy Mahila Divas) को आधिकारिक मान्यता कई वर्षों बाद 1975 में मिली। और 1977 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए 8 मार्च को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अवकाश के रूप में घोषित किया। वर्ष 1996 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक थीम (Theme) के साथ मनाने का निर्णय लिया गया और इसकी सबसे पहली थीम "सेलीब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्युचर (Celebrating the Past and Planning for the Future)"थी।

पिछले साल यानी 2023 की थीम (Theme) "डिजिटऑल: इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता (DigitAll: Innovation and technology for gender equality)" थी।

वर्ष 2024 की थीम क्या है

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक विशेष Theme यानी एक खास विचार जिसे हम आम भाषा में स्लोगन या नारा भी कहते हैं, के साथ मनाया जाएगा। इस साल की थीम है " समावेशन को प्रेरित करें" (Inspire Inclusion).

तो, "इंस्पायर इंक्लूजन या समावेशन को प्रेरित करें" का क्या मतलब है? (So, what does "Inspire Inclusion" mean?"

यह महिलाओं के लिए ऐसे वातावरण बनाने के बारे में है जहां हर महिला अपनी पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थितियों की परवाह किए बिना सम्मानित और शामिल महसूस कर सके और साथ ही साथ काबिलियत को भी बढ़ावा दे सके। यह बाधाओं को दूर करने और सभी महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर के बारे में है।

समावेशन को प्रेरित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

क्योंकि महिलाओं का समावेशन केवल एक अच्छी बात नहीं है; बल्कि देश की प्रगति के लिए एक आवश्यकता है। जब हम लिंग, नस्ल या सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर महिलाओं को अवसरों से वंचित रखते हैं, तो हम न केवल उनका अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों और समुदायों की वृद्धि और समृद्धि में भी बाधा डाल रहे हैं। जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, तो हम समाज को सशक्त बनाते हैं! अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी कार्यस्थल अधिक उत्पादक, नवीन और लाभदायक हैं। जो समुदाय विविधता को अपनाते हैं वे अधिक मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे मनाते हैं

विश्व भर में यह दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने का हर देश का अपना अलग-अलग तरीका होता है। कहीं राजकीय अवकाश, तो कही आधे दिन का अवकाश देकर मनाया जाता है। कई लोग इसे स्त्रियों को फूल या उनके सम्मान में तोहफा देकर मनाते हैं । हमारे देश भारत में इस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। उनके प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंग क्या है

यह हमारी पारंपरिक सोच (stereotype or traditional thinking) है कि गुलाबी रंग (Pink Color) लड़कियों और महिलाओं के लिए जबकि नीला रंग (Blue Color) लड़कों और पुरुषों के लिए है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो यह सही नहीं है।

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला वैश्विक अवसर वास्तव में तीन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है: बैंगनी (Purple), हरा (Green) और सफेद (White)। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) की वेबसाइट के अनुसार, बैंगनी (Purple), हरा (Green) और सफेद (White) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं।

1908 में यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ (WSPU) से रंगों की उत्पत्ति हुई। बैंगनी (Purple) न्याय और गरिमा का प्रतीक है; हरा (Green) आशा का प्रतीक है; सफेद (White) शुद्धता का प्रतिनिधित्व (हालांकि यह एक विवादास्पद अवधारणा है) करता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रयास तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं देखा जाता है। रोज नई नीति, नए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उसका सही ढंग से पालन नहीं होता। सही मायने में महिला सशक्तिकरण, तब होगा जब महिलाओं में कुछ करने का आत्मविश्वास होगा, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी ।

महिलाएं आज भी अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है, फिर वह चाहे शिक्षा हो या कार्यक्षेत्र या राजनीति क्यों ना हो। हमारा समाज आज भी किसी स्त्री के नेतृत्व में काम करने में एक संकोच महसूस करता है। जब तक महिलाओं में स्वयं अपने अधिकारों और अपने सम्मान को लेकर जागृति नहीं आएगी तब तक यह संभव नहीं है, कि वह अपने घरेलू अत्याचार (Domestic Abuse or Violence Violence), यौन उत्पीड़न (Sexual Abuse), मानसिक उत्पीड़न (Mental Harassment or Abuse) से मुक्ति पा सकेंगी। आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का मौन रहना कोई विकल्प नहीं है। अब विकल्प नहीं समाधान ढूंढ़ना है। अगर महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर है, तभी एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त (Nari Sashaktikaran or Mahila Sashaktikaran or Women Empowerment in Hindi) बनाना बहुत आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होता है। क्योंकि उनके नैतिक मूल्य एक अच्छे परिवार, समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र को विकास की ओर ले जाती है।

जहां एक प्रकार से महिलाओं के शोषित और कष्टप्रद जीवन के लिए पुरुष प्रधान समाज को दोषी मानते हैं। वहीं यह भी एक कड़वा सत्य है, कि महिलाएं स्वयं भी इसके लिये जिम्मेदार है। यह कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है, कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने स्त्री-शक्ति को अधिक सहजता से स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में भी व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य कई क्षेत्रों में महिलाओं ने परचम लहराया है। निश्चित रूप से यह महिला दिवस पर कुछ हद तक संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन ये भी सही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जागरूकता की जरूरत है। उन्हें उनके अधिकारों से परिचित करवाने की आवश्यकता है। उन्हें और अधिक स्वावलंबी बनाना है, ताकि वह अपना निर्णय खुद ले सके।

हर साल, महिला दिवस एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है. इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय

"डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी" है.

परिवर्तन का समय अब है! 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम "महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएं" । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024: 'महिलाओं में निवेश करें: प्रगति में तेजी लाएं'

एक स्टैंड लें और Invest In Women हैशटैग के साथ बातचीत में शामिल हों। यहां पांच प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं को पीछे न छोड़ा जाए यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है:

1. महिलाओं में निवेश: एक मानवाधिकार मुद्दा

समय समाप्त हो रहा है। लैंगिक समानता सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती बनी हुई है। महिलाओं में निवेश एक मानवाधिकार अनिवार्यता है और समावेशी समाज के निर्माण की आधारशिला है। महिलाओं की प्रगति से हम सभी को लाभ होता है।

2. गरीबी ख़त्म करना

2020 के बाद से कोविड महामारी, भू-राजनीतिक संघर्ष, जलवायु आपदाएं और आर्थिक उथल-पुथल ने अतिरिक्त 75 मिलियन लोगों को गंभीर गरीबी में धकेल दिया है। इससे 2030 तक 342 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे रह सकती हैं, जिससे तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाएगी। .

3 लिंग-उत्तरदायी वित्तपोषण लागू करना

संघर्षों और बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों के कारण, हाल के अनुमानों से पता चलता है कि 75 प्रतिशत देश 2025 तक सार्वजनिक खर्च पर अंकुश लगा देंगे। मितव्ययता महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ा देती है।

4. हरित अर्थव्यवस्था और देखभाल समाज की ओर स्थानांतरण

वर्तमान आर्थिक प्रणाली गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ाती है, जिसका महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैकल्पिक आर्थिक मॉडल के समर्थक हरित अर्थव्यवस्था और देखभाल वाले समाज की ओर बदलाव का प्रस्ताव करते हैं जो महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाता है।

5. नारीवादी परिवर्तन-निर्माताओं का समर्थन करना।

नारीवादी संगठन महिलाओं की गरीबी और असमानता से निपटने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। हालाँकि, वे ख़ाली चल रहे हैं और कुल आधिकारिक विकास सहायता का मात्र 0.13 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं।

हमें अपने अधिकार अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को समझना होगा तभी हम बना पाएंगे "नए भारत की नई तस्वीर" । वास्तव में महिला दिवस मनाया जाना तभी सिद्ध होगा

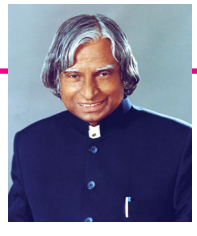

"एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होता है।"

– ए पी जे अब्दुल कलाम

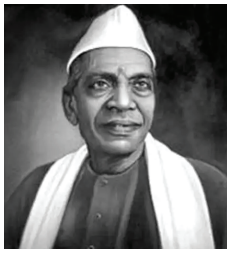

नर हो, न निराश करो मन को
कुछ काम करो, कुछ काम करो
जग में रह कर कुछ नाम करो
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो
कुछ तो उपयुक्त करो तन को
नर हो, न निराश करो मन को

– मैथिलीशरण गुप्त

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल

यूनुस आलम,
ब्यूरो चीफ़

रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के चलते एनसीआर में सफर करना लोगों के लिए बेहद आसान हो सकता है। रैपिड रेल तेज रफ्तार से लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाती है। दिल्ली मेरठ रूट के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बीच जल्द ही रैपिड रेल संचालन की प्लानिंग है। इसके लिए आरआरटीएस गाजियाबाद स्टेशन से रैपिड रेल प्रस्तावित ट्रैक पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट भी लाया जाएगा। इसमें एक तरफ आईजीआई एयरपोर्ट ना केवल जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा, बल्कि गाजियाबाद के आरआरटीएस स्टेशन से रैपिड रेल ट्रैक पर मेट्रो लोकल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसे मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी एमआरटीसी के तहत चलाने का प्लान है।

गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, परी चौक होते हुए मेट्रो नोएडा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। 72 किलोमीटर के रूट पर 25 स्टेशन बनाए जाने हैं। जिसे बाद में 38 स्टेशन तक बनाने की भी तैयारी है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों ने इसका प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें तीन विकल्पों पर विस्तृत चर्चा विमर्श के बाद सहमति बनी है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से जेवर एयरपोर्ट तक 25 स्टेशन बनाए जानें हैं। इसकी जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) को दी गई है। रैपिड रेल के तैयार होने के बाद एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्री सीधे रैपिड रेल से यात्रा कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा।

गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रैपिड रेल के रूट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी आ रहा है। लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुल मिलाकर रैपिड रेल के 8 स्टेशन बनेंगे। जिसमें पहला स्टॉपेज सेक्टर-16 सी में बनेगा। इसके अलावा चार मूर्ति, ईकोटेक-12, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-10, सेक्टर-12, नॉलेज पार्क- पांच में बनकर तैयार होगा।

ग्रेटर नोएडा में कुल 12 स्टेशन बनेंगे। पुलिस लाइन सूरजपुर, मलकपुर, ईकोटेक-दो, नॉलेज पार्क-तीन, गामा-वन, परी चौक, ओमेगा-दो, ईकोटेक-आईई, ईकोटेक-6, दनकौर में स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अभी तीन स्टेशन प्रस्तावित हैं। जिसमें यीडा नॉर्थ सेक्टर-18, यीडा सेंट्रल में सेक्टर-21, सेक्टर-35 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जीटीसी) पर रैपिड रेल के स्टेशन बनेंगे।

गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक बनने जा रहे आरआरटीएस/एमआरटीएस यानी रैपिड रेल और मेट्रो के स्टेशन बनाए जाने हैं। जिसमें 11 स्टेशन रैपिड रेल के बनाए जानें हैं, जबकि 14 स्टेशन मेट्रो के बनेंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक नॉन स्टॉप नमो भारत का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन महज 40 मिनट में एयरपोर्ट से एयरपोर्ट की दूरी तय करेगी। बताया जा रहा नमो भारत 140 की रफ्तार में चलेगी।

G.B.C 4.0 से UP की बदलेगी सूरत ?

साजिद अली
संवाददाता,
ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान किये गये प्रस्तावों के चौथे भूमि पूजन समारोह में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 14 हजार परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस परियोजना के आकार लेने पर प्रदेश में लगभग 34 लाख रोजगार सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई धारा निकली है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। विकसित भारत के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है, जिससे हर तरफ से विकास की खबरें सामने आ रही हैं। पहले चारों तरफ से एक ही खबर आती रहती थी कि अपराध के मामले सामने आए हैं। पीएम ने कहा कि हम जब यूपी को विकसित बनाएंगे, कहते थे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। अपराध के मामलों ने प्रदेश को विकास की राह को बंद कर दिया था। आज अपराध पर लगाम लगाकर यूपी को विकास की राह पर ले जाने में कामयाबी मिली है।

यूपीसीडा की करीब 1.50 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अब तक का सबसे बड़ा निवेश मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में G.B.C में 1.41 लाख करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की अधिकतर परियोजनाएं बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लगाई जाएंगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने के बाद कहा कि यूपी में विकास और विश्वास का माहौल बना है। आज यूपी में निवेश प्रस्ताव आते हैं तो खुशी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी वो राज्य है, जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज देश में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है, जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा।

यूपी में सुरक्षित निवेश की गारंटी है: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के शुभारंभ के लिए प्रदेश आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए हुए निवेशकों व उद्यमियों का भी स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी अपनी प्रतिभा और अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है।

10 साल में 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था

सीएम योगी ने कहा कि यह भूमि भगवान श्रीराम की है, गोपेश्वर श्रीकृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है, मां गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इसको प्राप्त हुआ है, यह धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है, यह उद्यम और उद्यमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है। इस संकल्प के साथ जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमने स्किल, स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आप सभी उद्यमियों का सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा।

यूपी के निवेश इंजन के रूप में गौतमबुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरणों का अहम रोल है। तीनों प्राधिकरण अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपये की 14 हजार परियोजनाओं की बुनियाद रखी जानी है। जिसमें अकेले गौतमबुद्ध नगर का बहुत बड़ा रोल है। तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में कुल मिलाकर दो लाख 95 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है। गौतमबुद्ध नगर में सबसे ज्यादा निवेश प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर जिले में तीन लाख नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को 60-60 हजार करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर लाने का लक्ष्य मिला था। तीनों प्राधिकरण ने इस लक्ष्य से ऊपर जाकर निवेश को जिले में लाने में सफलता हासिल की है। अकेले नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रुपये, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक और यमुना प्राधिकरण ने 60 हजार करोड़ रुपये के बदले 80 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव उतारेगा। गौतमबुद्ध नगर में इस इन्वेस्टमेंट आने के बाद रोजगार की बात करें तो जिले में तीन लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जिले में निवेशकों को सबसे ज्यादा यीडा क्षेत्र ने आकर्षित किया है। यहां पर बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

स्क्रैप की दुकान से अरबों तक का सफर

नोएडा में एक छोटी सी स्क्रैप की दुकान चलाने वाले ने कैसे इतना बड़ा सम्राज्य खड़ा कर दिया। कैसे महज तीन साल में रवि काना 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक बन बैठा। आखिर कैसे रवि काना ने अपना काला सम्राज्य खड़ा कर दिया। अब पुलिस रवि काना के पीछे क्यों पड़ी है। आखिर अब क्यों पुलिस उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसकी एक-एक संपत्ति को कुर्क करने में जुटी है। क्या रवि काना का सम्राज्य नोएडा, ग्रेटर-नोएडा या फिर यूपी तक ही सीमित है।

कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद नोएडा के गैंगस्टरों में एक नाम तेजी से उभरा है। यह नाम कुछ साल पहले तक स्क्रैप की छोटी सी दुकान करने वाले रवि काना का है। एक बार अनिल दुजाना का वरदहस्त क्या मिला, यह बदमाश तेजी से नोएडा एवं आसपास के अपराधियों का सिरमौर बन गया। यही नहीं, अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद उसके गैंग का मुखिया भी बन गया। फिलहाल गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने रेप के मामले में फरार चल रहे इस बदमाश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

इस मामले में पुलिस ने इसकी पत्नी मधु और सेक्रेटरी काजल झा समेत 16 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे इन सात वर्षों में ऐसा क्या हुआ, जिससे एक स्कूटर से चलने वाले कबाड़ी रवि काना के पीछे देखते ही देखते लग्जरी गाड़ियों का काफिला लग गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव का रहने वाला रवि काना हाल तक नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में कबाड़ का काम करता था। कभी अनिल दुजाना का था राइट हैंड रवि काना का भाई पहले कभी अनिल दुजाना के संपर्क में था। इसी रंजिश की वजह से गैंगस्टर सुंदर भाटी के लोगों ने साल 2015 में हरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद रवि काना खुद अनिल दुजाना से मिल गया और देखते ही देखते उसने दुजाना का राइट हैंड बन गया। नोएडा पुलिस के मुताबिक इसके बाद यह बदमाश खुले तौर पर सरिया लदे ट्रकों को लूटने लगा। इसके बाद साइट मैनेजरों को डरा धमका कर पूरा वजन दर्ज करा देता था। यही नहीं, गैंग के बदमाश बाजार भाव से ऊंचे रेट पर व्यापारियों को उतारा गया सरिया बेचते थे. इससे कमाई बढ़ी तो इस गैंग ने जिले में संचालित कंपनियों, फैक्टरियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और मनमाने तरीके से स्क्रैप का ठेका लेने लगे। इससे महज तीन साल में ही इसकी संपत्ति 97 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। पुलिस अधिकारियों की मानें तो इस बदमाश ने कुछ बेनामी कंपनियां भी खोल रखे हैं। इन्हीं कंपनियों के नाम से यह सस्ता टेंडर डालता था और फिर तमाम कंपनियों को अपने पक्ष में टेंडर छोड़ने के लिए मजबूर करता था। बताया जा रहा है कि इस बदमाश के कई अफसरों और सफेदपोश लोगों से भी गहरा नाता है। इसके दम पर ही इसने पिछली बार जेवर विधानसभा से अपनी भाभी बेबन नागर को सपा का टिकट भी दिलाया था। पिछले दिनों जब इसने ग्रेटर नोएडा के गामा सेक्टर में गृहप्रवेश किया तो उसमें बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन भी किया था। इसमें कई राजनेता और अफसर पहुंचे थे। फिलहाल तो यह बदमाश फरार है, लेकिन इसकी गैंग के चार बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है।

रवि काना का नागालैंड कनेक्शन

विदेश में बैठा रवि काना भले ही पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया हो लेकिन गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे-जैसे उसकी कंपनी और गैंग के सदस्यों की संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक अरब से अधिक की संपत्ति के साथ ही गैंग के अब तक पचास से अधिक वाहन भी जब्त हो चुके हैं। रवि काना गैंग के नागालैंड कनेक्शन की अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। गैंग के पास से बीस से अधिक कामर्शियल वाहन ऐसे मिले हैं, जो नागालैंड में पंजीकृत हैं। जिनकी कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक है। गाड़ियों पर लोन भी नागालैंड की विभिन्न बैंक से हुआ है। पुलिस उधेड़बुन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो गैंग ने दो हजार से अधिक किलोमीटर दूर नागालैंड के नंबरों पर वाहनों की खरीद की और लोन कराया। रवि काना के पास छह से दस पहिया तक के बीस से अधिक ऐसे कामर्शियल वाहन हैं, जो नागालैंड में पंजीकृत हैं। वाहनों की कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। नागालैंड नंबर के वाहनों की जानकारी वहां की पुलिस को भेजकर जानकारी मांगी गई है।

रवि और गैंग पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोठी पर पहुंचकर जांच की थी। उस दौरान पता चला था कि कोठी किराए पर थी। चल रही जांच में पता चला है कि कोठी के पते पर गैंग की कुछ कंपनी पंजीकृत हैं

रवि की पत्नी मधु गिरफ्तार

यह भी देखा जाएगा कि वाहनों पर लोन कंपनी के नाम से है या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर। संभावना जताई जा रही है कि गैंग ने वहां पर भी कुछ संपत्ति खरीदी हो। कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने रवि की पत्नी मधु को गिरफ्तार किया था। वह एक माह तक बैंकाक में रहने के बाद भारत लौटी थी। उससे पूछताछ में भी पुलिस को गैंग की संपत्तियों के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। उन संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नागालैंड के नंबर पर मिले वाहनों के जांच कराई जा रही है।

अस्सी करोड़ की कोठी की दोबारा शुरू हुई जांच

रवि अपने परिवार के साथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी की एक कोठी में रहता था। कोठी की कीमत लगभग अस्सी करोड़ रुपये बताई गई थी। रवि और गैंग पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोठी पर पहुंचकर जांच की थी। उस दौरान पता चला था कि कोठी किराए पर थी। चल रही जांच में पता चला है कि कोठी के पते पर गैंग की कुछ कंपनी पंजीकृत है। ऐसे में पुलिस दोबारा से कोठी के मालिकाना हक की जांच कर रही है। आपको बता दें पिछले लगभग एक माह के दौरान पुलिस ने रवि काना गैंग की 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

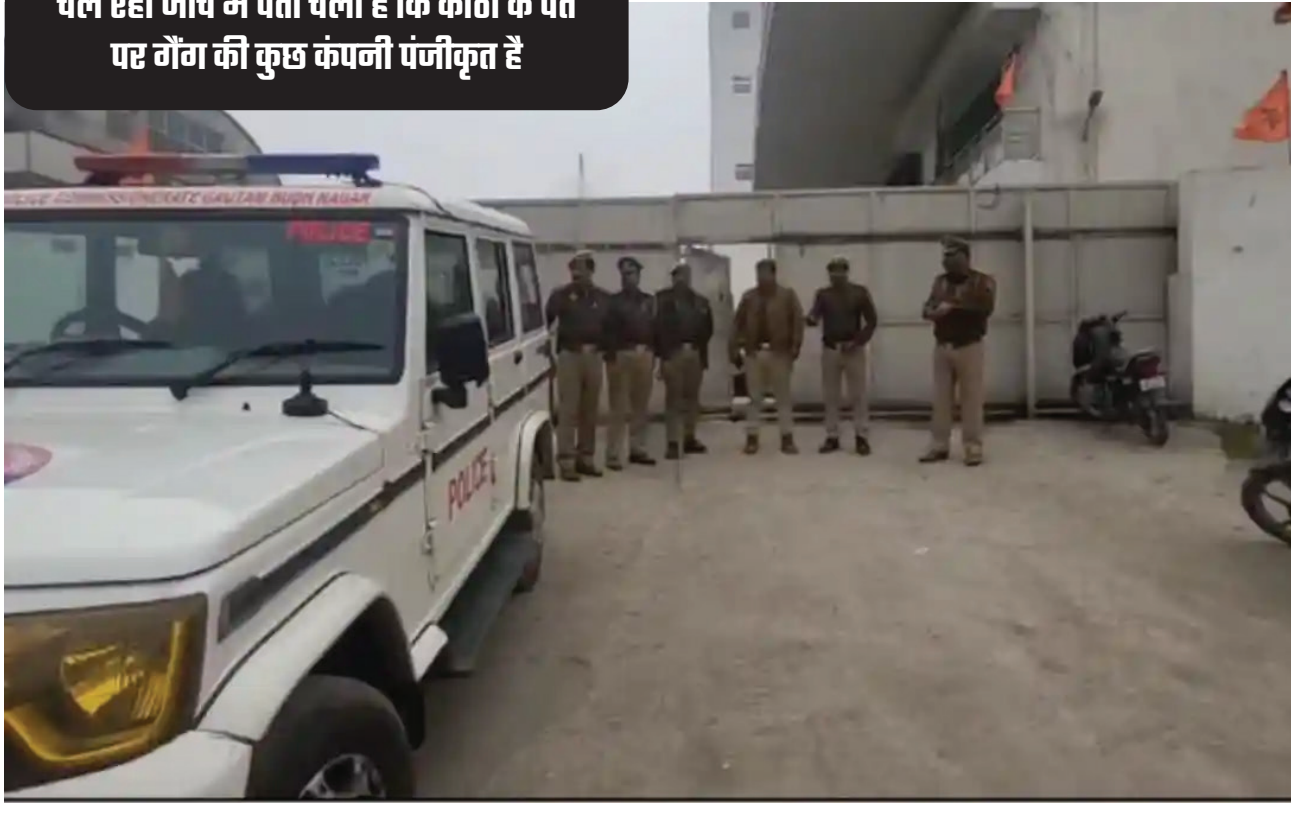

नफे सिंह राठी हत्याकांड, गहरी साजिश, विदेश तक तार

यूनुस आलम,
ब्यूरो चीफ़

हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्या नफे सिंह राठी की हत्या ने पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को ताजा कर दिया है। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी ठीक उसी प्रकार बदमाशों ने नफे सिंह राठी को मौत को घाट उतार दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी ठीक इसी अंदाज से की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी जिसमे उसकी मौत हो गई थी। वहीं नफे सिंह राठी की गाड़ी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में कई घंटे बीत जाने का बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है।

कैसे की गई नफे सिंह राठी की हत्या

जानकारी के अनुसार नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सफेद रंग की आई-10 गाड़ी में सवार पांच बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौके पर दो दर्जन से ज्यादा फायरिंग की गई है। फायरिंग इतनी जबरदस्ती की गाड़ी के शीशे और गाड़ी की लोहे की बॉडी को पार कर गोलियां अंदर बैठे नफे सिंह राठी और अन्य लोगों को जा लगी। बताया जा रहा है कि नफेसिंह राठी की गर्दन पर दो गोलियां लगी। इतना ही नहीं उनकी कमर और अन्य जगहों पर भी गोलियों के निशान बताएं गए हैं । फॉर्च्यूनर गाड़ी पर भी गोलियों के कई निशान साफ तौर से देखे जा सकते हैं।

वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार

नफे सिंह राठी की हत्या को अंजाम देकर हमलावर बड़ी ही आसानी से मौके से फरार हो गए। इमले में नफे सिंह राठी के साथ उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई। जिस समय उन पर हमला किया गया तो गाड़ी में 5 लोग सवार थे। नफे सिंह ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे। शाम करीब पांच बजे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। बराही रेलवे फाटक पर हमलावरों ने इस वारदा को अंजाम दिया।

पुलिस के हाथ अभी भी खाली

घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया। जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष एवं बहादुरगढ़ से पूर्व में दो बार विधायक रहे नफे सिंह राठी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके समर्थक जयकिशन दलाल मांडौठी की भी मोके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी को भी कई गोलियां लगी हैं। उनकी हालत भी कभी गम्भीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू करवाई गई। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। 22 फरवरी को मनाया था जन्मदिन22 फरवरी को इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी का जन्मदिन था। चार दिन पहले अपने परिवार और समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। लेकिन किसी को भी ये अहसास नही था कि ये उनका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। पिता को खोने से बदहवास बेटे ने रोते हुए कहा कि उन्हे नही पता था कि उनके पिता के साथ उनका

ये आखिरी जन्मदिन होगा। उन्होंने कहा कि आज बहादुरगढ़ ने अपना रखवाला खो दिया है। जितेन्द्र राठी ने कहा कि पिछले 6-7 महीने से उन्हे हमले का इनपुट मिल रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी लेकिन उन्हे सुरक्षा नही दी गई। जितेन्द्र ने कहा कि उनके पिता ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से मिलकर भी सुरक्षा देने के लिए बात की थी लेकिन उन्होंने भी उन्हे सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। जितेन्द्र ने उनके पिता की हत्या के लिए जिम्मेदारों लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी कही है।

जाट समुदाय से ताल्लुक चौटाला परिवार के करीबी

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का जन्म बहादुरगढ़ के जाटवाड़ा गांव में हुआ था. वह प्रदेश के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला के बेहद करीबी थे.

जब इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD में फूट पड़ी थी और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला और उनके दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय ने जेजेपी नाम से अलग पार्टी बना ली तब भी नफे सिंह राठी ने ओपी चौटाला का साथ नहीं छोड़ा था और दुष्यंत का खुलकर विरोध किया था.

INLD के नेताओं और पार्टी कैडर में मजबूत पकड़

नफे सिंह राठी INLD के पुराने नेताओं में से एक थे. उनकी पार्टी कैडर में मजबूत पकड़ थी. वह ग्राउंड लेवल पर कॉफी एक्टिव थे. नफे सिंह राठी ने 1996 में बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी. दूसरी कामयाबी साल 2000 में मिली, जब राठी ने जनरल कैटेगरी में INLD के टिकट पर बहादुरगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल किए. इस बार वो 49.1 फीसदी वोटों से जीतकर विधायक बने. नफे सिंह राठी दो बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे.

जाटलैंड में नफे सिंह राठी की लोकप्रियता

जाटलैंड में लोकप्रिय नेता रहे नफे सिंह राठी को पार्टी का दामन तब छोड़ना पड़ा जब 2014 में INLD ने उन्हें बहादुरगढ़ से टिकट नहीं दिया. इसके बाद नफे सिंह राठी बीजेपी में चले गए, लेकिन जब बीजेपी ने भी उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा. हालांकि 2018 में उनकी INLD में वापसी हो गई. INLD में वापसी के बाद राठी को खुद को आजमाने का मौका दोबारा दिया गया. हरियाणा विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के एक साल बाद जनवरी 2020 में राठी को पार्टी की हरियाणा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. उन्होंने बीरबल दास ढालिया की जगह ली, जिन्हें इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था.

पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर रहे थे राठी

2019 के चुनाव से पहले INLD बिखर गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी (जननायक जनता पार्टी, Jannayak Janta Party) बनी, जिसके नेता दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं. वहीं, दूसरे बेटे अभय चौटाला INLD को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगे रहे, जिसके चलते उन्होंने बहादुरगढ़ से दो बार के विधायक रहे नफे सिंह राठी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था.

नफे सिंर राठी पर पिछले साल दर्ज हुआ था केस

नफे सिंह राठी को जनवरी 2023 में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें पूर्व बीजेपी मंत्री मांगे राम राठी के बेटे जगदीश राठी की आत्महत्या मामले में आरोपी बनाया गया था. उनपर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. नफे सिंह राठी की हत्या के आरोपियों की लिस्ट में जगदीश राठी का बेटा गौरव राठी और भाई सतीश राठी का नाम भी शामिल हैं

सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, भारत टेक्स-2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम में से एक 'भारत टेक्स-2024' का उद्घाटन किया। भारत टेक्स-2024। 26 फरवरी से शुरू होकर बृहस्पतिवार 29 फरवरी तक चले टेक्स्टाइल इवेंट की धूम मची। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घघटन कर जो बातें कहीं वो इस उद्योग के भविष्य के लिए बेहद अहम है। टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा भारत टेक्स-2024: पीएम मोदी पीएम मोदी ने इस एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद कहा कि आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है. इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई हैं. भारत टेक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है. भारत टेक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है.

टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है. फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर मुख्य फोकस पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में पहले ही बताया गया था कि प्रधानमंत्री के '5एफ विजन' से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर मुख्य फोकस रखा गया है. पीएम मोदी ने आज कार्यक्रम में भी कहा कि Five F की ये यात्रा Farm, Fibre, Factory, Fashion से होते हुए Foreign तक जाती है. हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को Five F के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं.

नारी शक्ति का टेक्सटाइल सेक्टर के विकास में बड़ा योगदान- पीएम मोदी कपड़े बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा हैं. टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है. पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने जो भी प्रयास किए, उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है.

विकसित भारत बनाने में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम रहे हैं. हम 4T के तहत यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं.

संदीप ओझा,
संपादक

CAA आ रहा है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि केंद्र सरकार सीएए को जल्द अधिसूचित किए जाने की तैयारी में है। 11 दिसंबर, साल 2019 को अधिनियमित सीएए पूरे देश में चर्चा और व्यापक विरोध का विषय रहा है। इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जो लोग सीएए के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं। उनको एक बार कानून का मसौदा जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आ सके की आखिर असल कानून की हकीकत क्या है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नोटिफिकेशन का इंतजारअनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लागू कर सकती है। सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे शुरू हुई फिर चर्चादरअसल, फरवरी महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। जब पहली बार पेश हुआ बिलसबसे पहले नागरिकता संशोधन बिल साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया, यहां से तो ये बिल पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। दोबारा मोदी सरकार के रिपीट होने के बाद साल 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया. जिसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

सीएए के लागू होने में देरी के कारणसीएए के लागू होने में देरी के कई कारण हैं। शुरुआत में इसके विरोध के कारण पूरे देश में सीएए को लेकर बहस तेज हो गई। इसे लेकर कई राज्यों में हिंसा भी देखने को मिली। जिसमें असम और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं, जहां के व्यापक प्रदर्शनों ने चिंताएं बढ़ा

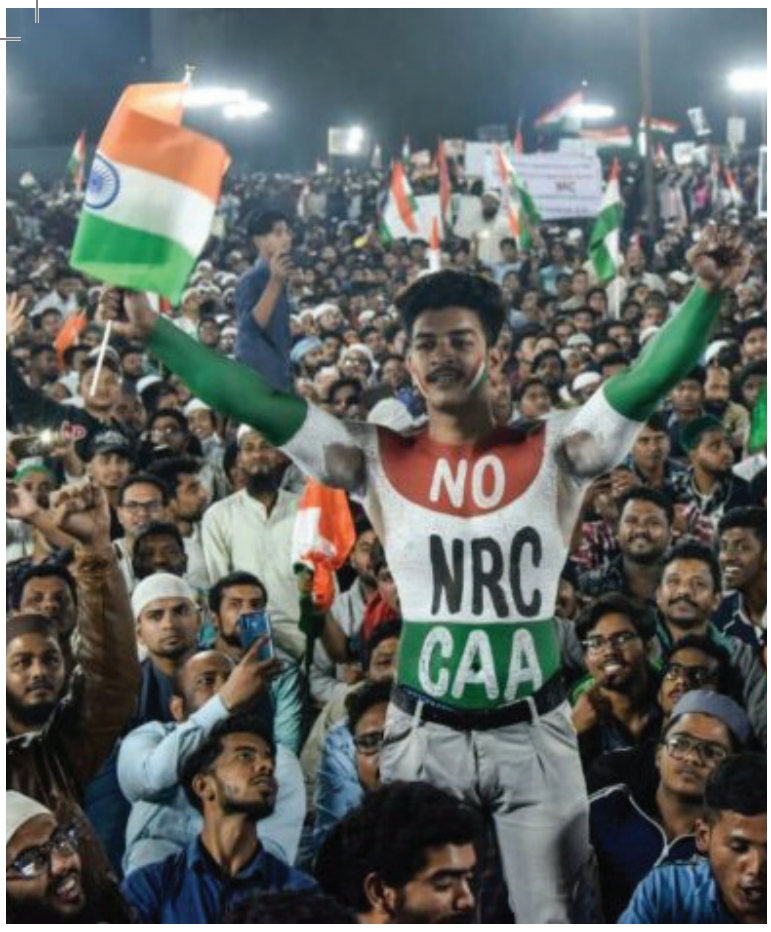

दी थीं। इसके अलावा दिल्ली के शाहीन बाग में धरना, असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गयीं और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बती बौद्धों जैसे कुछ उत्पीड़ित समूहों को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध-प्रदर्शन थम गए थे। फिर सीएए पर लंबी खामोशी बनी रही। संसद में पारित होने के चार साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो सका। सवाल ये भी उठते रहे कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हुई? साल 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है।

केंद्र के पास नागरिकता देने का अधिकार

नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है. पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक, जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वह साल बताना होगा, जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। सरकार ने 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले दो साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है. जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है, उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है. सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है. गृह मंत्री का कहना है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है. तीन देश के गैर-मुस्लिमों के लिए खास छूटकानून भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है. लेकिन, नागरिकता संशोधन कानून में इन तीन देशों के गैर-मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों।गैर-मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार नॉर्थ-ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है. इसकी वजह भी सामने आई है. दरअसल, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी. वहां युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया. लेकिन, कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है. - पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे. इन लोगों को वैसे तो अलग-अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज्यादा करीब लगा और वे वहीं बसने लगे. चूंकि पूर्वोत्तर

राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है इसलिए भी वहां से लोग आते हैं.

मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतिया जैसी ट्राइब मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वे पीछे रहे गए. हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया. इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं. यहां तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं. अब अगर सीएए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी. दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे. यही डर है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहा है.

असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं. यह दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था. यही हालात बाकी राज्यों के हैं.

विपक्ष का धर्म को लेकर सवालविपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ छह धर्मों से जुड़े लोगों तक ही क्यों सीमित है. मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और यह सिर्फ तीन देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है? केंद्र सरकार का दावा है कि इन छह धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है. मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं हैं.

विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं. वहीं, बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है. विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है. वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली, तो उनके राज्य के संसाधन बंट जाएंगे. एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा. पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं. इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं. - इन सातों राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं. इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है लेकिन कुछ दशकों से यहां दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा. खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहां आने लगे. वादा कर रहे हैं पूरा: गृह मंत्रीगृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव से पहले CAA लागू करने का वादा किया था. इसके पारित होने के करीब तीन साल बाद यानी 29 नवंबर, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और इसे कोई

नहीं रोक सकता है. गृह मंत्री शाह ने तुष्टिकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला था. 3 जनवरी को एक मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने सीएए के नियम तैयार कर लिए हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार के सूत्र का कहना था, एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है. पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है. 28 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि 7 दिन में CAA के नियम आ जाएंगे. उन्होंने इसे जल्द लागू होने की गारंटी भी दी थी. शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. वे बंगाण लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं. ये इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा है.

वहीं, आम चुनाव से पहले सीएए लागू करने की चर्चा को विपक्षी दल राजनीति के तौर पर देख रहे हैं. टीएमसी नेता शशि पांजा कहते हैं कि हमेशा की तरह बीजेपी सीएए को लेकर अपनी पुरानी रणनीति का सहारा ले रही है. जब वो (शांतनु ठाकुर) ये बयान देते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है. हमारी सीएम ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बीजेपी के लिए एक चुनावी मुद्दा है. वह लोगों के लिए जिस तथाकथित नागरिकता की बात कर रहे हैं, वे पहले से ही इस देश के नागरिक हैं. ममता बनर्जी का विरोधपश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी शुरू से ही सीएए का विरोध कर रही है. टीएमसी ने सीएए नियमों की जल्द अधिसूचना की खबरों पर मंगलवार को चिंता जताई और आरोप लगाया कि इस तरह की अटकलों का उद्देश्य जनता को गुमराह करना और संसदीय चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी फैलाना है. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सीएए का विरोध करेंगे. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, हम उससे चिंतित हैं. जिस तरह से राज्य के निवासियों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का एक सुनियोजित हिस्सा है. TMC सीएए लागू करने के केंद्र के प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी. हम इसे चुनाव से पहले बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी का हिस्सा मानते हैं

यूनुस आलम,
ब्यूरो चीफ़

AAP विधा AAP विधायक दोषी, केजरीवाल की मुसीबत यक दोषी, केजरीवाल की मुसीबत

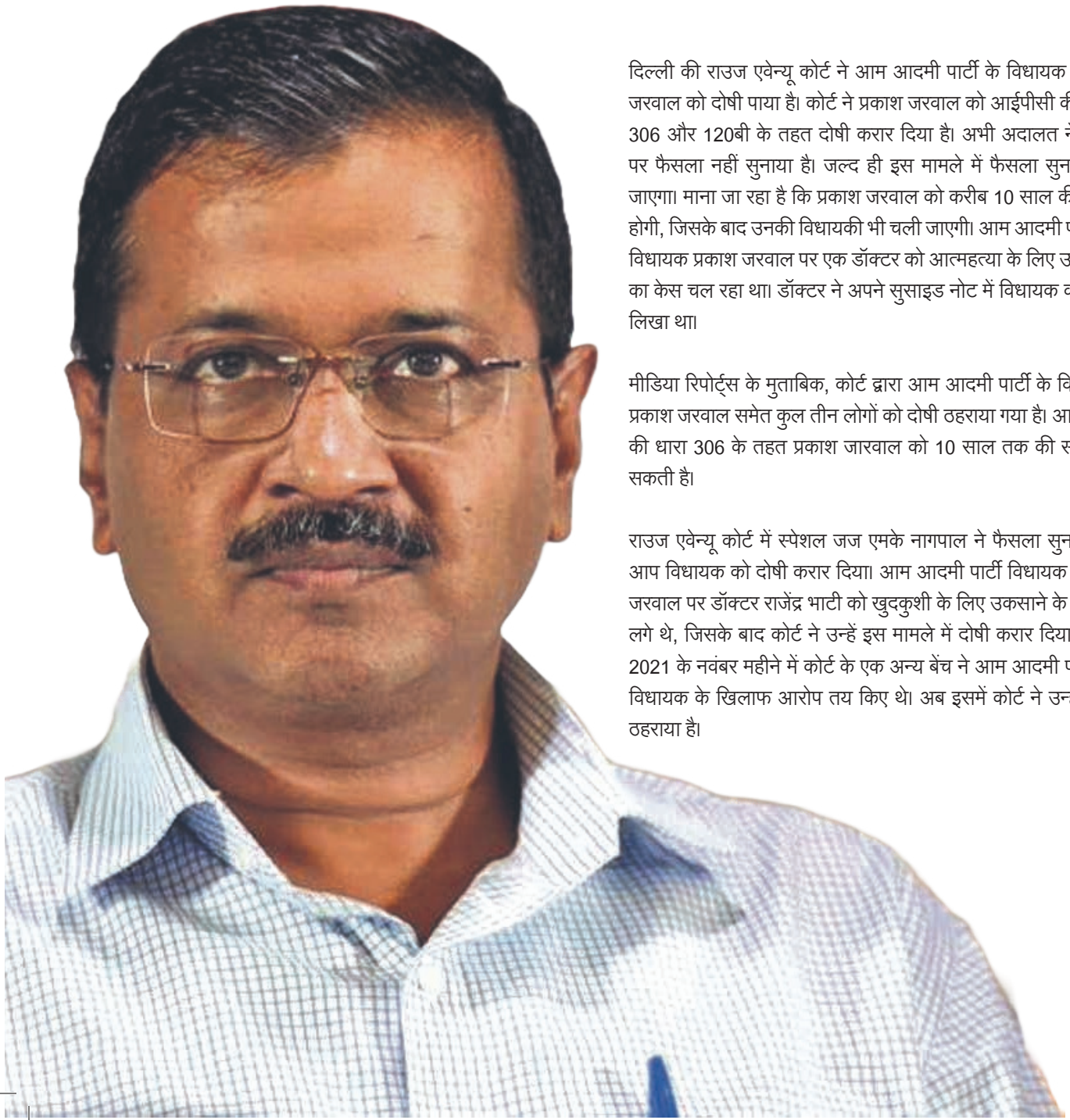

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दोषी पाया है। कोर्ट ने प्रकाश जरवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी करार दिया है। अभी अदालत ने सजा पर फैसला नहीं सुनाया है। जल्द ही इस मामले में फैसला सुना दिया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रकाश जरवाल को करीब 10 साल की सजा होगी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल पर एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा था। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में विधायक का नाम लिखा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल समेत कुल तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रकाश जारवाल को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाते हुए आप विधायक को दोषी करार दिया। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया। साल 2021 के नवंबर महीने में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब इसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है।

डॉक्टर का सुसाइड नोट

बता दें कि दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है। 18 अप्रैल 2020 को दिल्ली के नेब सराय इलाके में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेन्द्र सिंह ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से एक 2 पेज का सुसाइड नोट मिला था जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए इलाके के विधायक प्रकाश जरवाल और उनके सहयोगी कपिल को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें लिखा था, "मेरा इस इलाके में एक क्लीनिक है और मेरे कुछ वाटर टैंकर दिल्ली जल बोर्ड में किराए से चलते थे, लेकिन एमएलए प्रकाश जरवाल और उसका सहयोगी कपिल नागर मुझसे हर टैंकर के हिसाब से पैसे माँगने लगे। कुछ पैसे दिए भी गए लेकिन बाद में मेरे सभी टैंकर प्रकाश जरवाल ने दिल्ली जल बोर्ड से हटवा दिया।"

सुसाइड नोट में लिखा था, "टैंकरों को दिल्ली जल बोर्ड से हटवाने के बाद जब उन्हें ओखला के दिल्ली जल बोर्ड के लगवाया गया तो टैंकरों को वहाँ से भी प्रकाश जरवाल द्वारा हटवा दिया गया।" नोट के अनुसार प्रकाश जरवाल और उसके सहयोगी से उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी और धमकियों के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। जानकारी के मुताबिक, विधायक ने डॉक्टर से पिछले 5 सालों में 5 लाख रुपए लिए भी थे। डॉक्टर उन्हें रुपए देते रहे, ताकि उनके परिवार को परेशान न किया जाए। लेकिन, फिर भी विधायक व उनके सहयोगियों द्वारा बार-बार रुपए की माँग की गई। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में अपनी अंतिम इच्छा यही बताई है कि विधायक व उसके साथी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

प्रकाश जरवाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी के मामले में वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन पर राजद की एक महिला के शोषण करने का भी आरोप लगा था। वो सीएम केजरीवाल के साथ 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' में भी जुड़े हुए थे।

साजिद अली
विशेष संवाददाता

मोतियों की माला का कारोबार 20 देशों में बंपर डिमांड

कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो फिर आपने क्या पढ़ाई की, क्या सीखा, मायने नहीं रखता है। यह लाइन खुशबू पर पूरी तरह से लागू होती है। खुशबू ने जिस क्षेत्र में शिक्षा ली, उसमें नौकरी नहीं की। एनसीआर के ही एक गांव में मोती की माला बनते हुए देखी। वहां से हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में काम करने की ठान ली। परिवार किसी अच्छी कंपनी मे नौकरी करने के लिए खुशबू से जिद करता रहा लेकिन उन्होंने वह किया जो उनको अच्छा लगा। मोती की मालाओं के साथ हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स को उन्होंने 20 से ज्यादा देशों में पहुंचाया। आज खुशबू की कंपनी का टर्नओवर करोडों में है। खुशबू के माता पिता भी इस बात पर गर्व करते हैं। खुशबू के संघर्ष का सफर आसान नहीं रहा है।

मोती की माला का खड़ा किया कारोबार, अब दे रही हैं रोजगार, 20 से अधिक देशों में पहुंचा रही हैंडीक्राफ्ट आइटम सेक्टर-76 की आम्रपाली सिलिकॉन सिटी सोसायटी में रहने वाली खुशबू सिंह ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। लेकिन उनको पहचान देश विदेश के हैंडीक्राफ्ट बाजार से मिली। 40 वर्ष की खुशबू पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल तक नौकरी नहीं मिली। भटकते हुए एनसीआर के एक गांव में मोती की माला बनते हुए देख ली। यह काम ग्रामीण महिलाएं कर रहीं थीं। खुशबू ने इसी काम को आगे ले जाने का विचार किया। 4500 रुपये के वेतन पर एक हैंडीक्राफ्ट कंपनी में नौकरी 2007 में शुरू की।

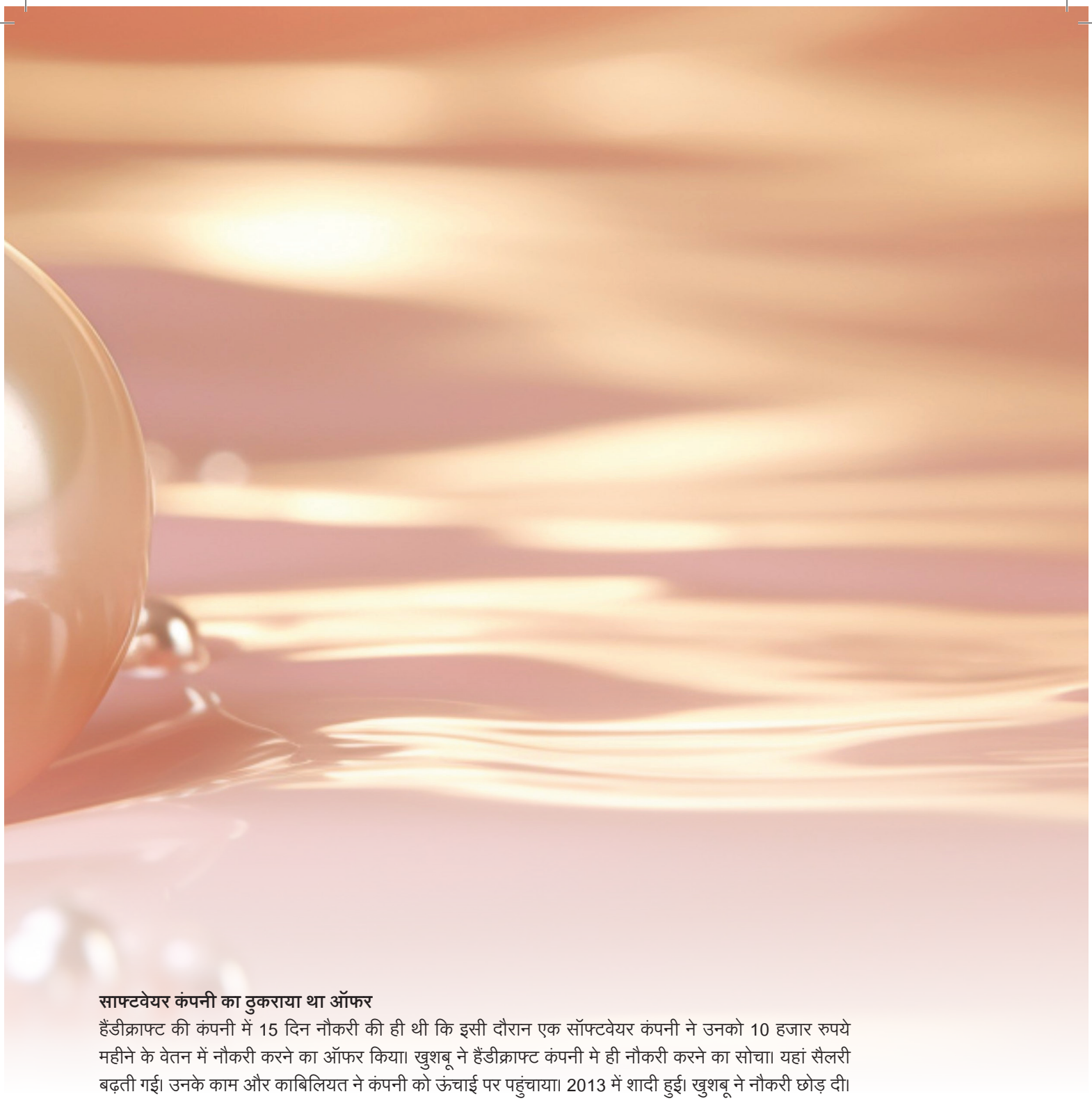

साफ्टवेयर कंपनी का ठुकराया था ऑफर

हैंडीक्राफ्ट की कंपनी में 15 दिन नौकरी की ही थी कि इसी दौरान एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने उनको 10 हजार रुपये महीने के वेतन में नौकरी करने का ऑफर किया। खुशबू ने हैंडीक्राफ्ट कंपनी मे ही नौकरी करने का सोचा। यहां सैलरी बढ़ती गई। उनके काम और काबिलियत ने कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाया। 2013 में शादी हुई। खुशबू ने नौकरी छोड़ दी। 2017 में खुद की कंपनी शुरू की। 6 सालों में कंपनी का सालाना टर्नओवर अब 9 करोड़ रुपये से ज्यादा है। परिवार में दो बेटियां और पति हैं।

महिलाओं को दिया रोजगार

मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, एटा समेत कई और जिलों में तैयार किया जाने वाला हैंडीक्राफ्ट का कच्चा माल अपनी कंपनी में मंगाया, कस्टमर से बात और ऑन डिमांड उसको मोतियों और अन्य चीजों से सजाया। इसके बाद सप्लाई करने का काम किया। अब खुशबू ऑन डिमांड यह माल तैयार करातीं हैं। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पहले से कच्चा माल तैयार कराया जाता है। इससे 5 जिलों के 10 गांवों की 150 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है।

जामनगर में अंबानी परिवार का जश्न

पूजा मिश्रा,
उपसंपादक़

मार्च का महीना अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग फंक्शन की धूम से शुरू होगा। इस शाही फंक्शन में बॉलीवुड हस्तियों के साथ ही हॉलीवुड और बिजनेस और दुनियाभर की मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। प्री-वेडिंग फंक्शन की तैयारियां और जानकारियों ने दुनिया भर का ध्यान इस जश्न की तरफ खींचा है । क्योंकि दुनिया भरे के नामचीन मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

अन्न सेवा में 51 हजार स्थानीय लोगों को आमंत्रित गया है। मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट ने खुद गांववालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। अन्न सेवा में राधिका की मां शैला, पिता वीरेन मर्चेंट और नानी भी शामिल हुईं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री-वेडिंग फंक्शन 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होना है।

रिलायंस रिफाइनरी के गांवों में हुए कार्यक्रम

मंगलवार की रात परिवार ने जामनगर के आसपास के गांवों में लोक डायरा (भजन-लोकगीत) और भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में अनंत अंबानी भी शामिल हुए। इस मौके पर गागवा गांव के लोगों ने हालारी पगड़ी पहनाकर तो नवानिया गांव में महिलाओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया।

जामनगर में खावड़ी के पास रिलायंस रिफाइनरी है। इसी के चलते अंबानी परिवार ने आसपास के कई गांवों में यह कार्यक्रम रखा था। गांव वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोक डायरा और भोज का कार्यक्रम कई गांवों में रखा गया था। खुद अनंत अंबानी ने कुछ गांवों में शिरकत की। इस दौरान गांववालों ने उनका जगह-जगह भव्य स्वागत किया।

आशीर्वाद के लिए अन्न सेवा का आयोजन

अंबानी परिवार ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व समारोह के लिए स्थानीय समुदाय का आशीर्वाद मांगने के लिए अन्न सेवा का आयोजन किया है। भोजन के बाद उपस्थित लोगों ने पारंपरिक लोक संगीत का आनंद उठाया। प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी गायकी से समां बांध दिया।

परिवार में अन्न सेवा की पुरानी परंपरा

अंबानी परिवार में अन्न सेवा की परंपरा पुरानी है। शुभ अवसरों पर अंबानी परिवार अन्न सेवा करता रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में था तब भी अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी की अगुवाई में रिलायंस फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम चलाया था। पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनंत अंबानी ने अपने विवाह-पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा की है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व कार्यक्रम का आयोजन एक से तीन मार्च तक चलेगा। इन तीन दिनों में देश-दुनिया की नामचीन हस्तियां आयोजन में शिरकत करेंगी। इस प्री-वेडिंग प्रोग्राम पर पूरे देश की नजर है। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है।

1 से 3 मार्च तक होगा प्री-वेडिंग फंक्शन

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री-वेडिंग फंक्शन 1 से 3 मार्च तक जामनगर के रिलायंस ग्रीन्स में होना है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश-विदेश की कई मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए जामनगर में सभी इंतजाम किए जा रहे हैं।

प्री वेडिंग में आने वाले मेहमनों की पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा। फूड मेन्यू में उन चीजों को अवॉइड या कम से कम रखा जाएगा, जिसे वो अवॉइड करते हैं। इसलिए प्री-वेडिंग में आने वाले मेहमानों से उनकी फूड च्वाइस मांगी गई है। हर एक मेहमान की डाइट का ख्याल रखा जाएगा।

65 शेफ की टीम तैयार करेगी पकवान

प्री-वेडिंग बैश के लिए इंदौर से करीब 65 शेफ के आने की सूचना है। इवेंट में इंदौरी खाने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा मैक्सिकन, पारसी, थाई, जैपनीज, आदि फूड भी मेहमानों के लिए परोसे जाएंगे। करीब 2500 डिशेज का इंतजाम होगा। इन सबके साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि तीन दिनों में कोई भी डिश रिपीट न हो।

लंच के लिए होंगे 225 पकवान

2500 डिशेज में से 75 तरह की चीजें ब्रेकफास्ट में शामिल होंगी। लंच के लिए 225 और डिनर के कम से कम 85 पकवान रखे जाएंगे। बाकी खाने की चीजें स्नैक्स में डाली जाएंगी। इंदौर के पकवानों में स्पेशल इंदौरी मसाले डाले जाएंगे। 28 फरवरी तक पहुंचकर शेफ वहां ट्रायल करेंगे। इसके बाद 1 मार्च से मेहमानों को खाने की चीजें परोसी जाएंगी।

कौन होगा गेस्ट?

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग फंक्शन में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी है. इस फंक्शन में मार्क जुकरबर्ग,बिल गेट्स, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत को भी गेस्ट के तौर पर इंवाइट किया है. इसके अलावा खबर है कि रणवीर-आलिया और सिंगर रिहाना,अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ सेलिब्रेशन में परफॉर्म करेंगे. अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी. शादी से पहले दोनों का प्री-वेडिंग फंक्शन का ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है.

अंटार्कटिक में पहली बार मिला बर्ड फ्लू

जानें क्या है ये बीमारी और कितनी खतरनाक

निर्मल गौड़,
उप संपादक

हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक में बर्ड फ्लू के पहले मामले की पुष्टि की है। यह पहली बार है जब अंटार्कटिक की मेनलैंड पर बेहद खतरनाक बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। Bird Flu को एवियन फ्लू भी कहा जाता है जो इन्फ्लूएंजा (फ्लू) का एक प्रकार है। यह ज्यादातर जंगली जल पक्षियों को संक्रमित करता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें-

अंटार्कटिक (Antarctica) बेस प्रिमावेरा के पास मृत मिले स्कुआ समुद्री पक्षी के नमूनों में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने वायरस की पुष्टि की है। इस मामले के सामने आने के बाद जेंटू पेंगुइन समेत आसपास के द्वीपों पर H5N1 एवियन फ्लू (Bird Flu) के खतरे को उजागर किया है, जिसने हाल के महीनों में दुनिया भर में पक्षियों की आबादी को नष्ट कर दिया है। इस बारे में सीएसआईसी ने एक बयान में कहा कि, "विश्लेषण से पता चला है कि पक्षी एवियन इन्फ्लूएंजा के एच5 सब-वेरिएंट से संक्रमित थे और मृत पक्षियों में से कम से कम एक में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस था।"

वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यह पहली बार है, जब अंटार्कटिक की मुख्य भूमि पर घातक प्रकार के बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जो दक्षिणी क्षेत्र की विशाल पेंगुइन के लिए संभावित खतरा है। आइए जानते हैं क्या है बर्ड फ्लू और इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें-

क्या है बर्ड फ्लू?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक बर्ड फ्लू, जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है, इन्फ्लूएंजा (फ्लू) का एक प्रकार है, जो ज्यादातर जंगली जल पक्षियों को संक्रमित करता है। हालांकि,यह घरेलू पक्षियों जैसे मुर्गी और अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। यह इन्फ्लूएंजा ए टाइप वायरस का स्ट्रेन है।

इतना ही नहीं बर्ड फ्लू लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि, इसके मामले काफी कम ही देखने को मिलते हैं। इंसानों को प्रभावित करने वाले इसके सबसे आम सबटाइप में A(H5N1), A(H7N9) और A(H9N2) शामिल हैं। इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर फ्लू जैसी बीमारी तक हो सकते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर या मौत भी हो सकती है।

बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है?

लोगों में बर्ड फ्लू के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। इनमें सामान्य फ्लू के लक्षण शामिल हो सकते हैं जैसे:-

दस्त
खांसी
उल्टी आना
आंखें लाल होना
गला खराब होना
भरी हुई या बहती हुई नाक
शरीर और मांसपेशियों में दर्द
100 डिग्री फारेनहाइट (37 डिग्री सेल्सियस) या इससे अधिक का बुखार

बर्ड फ्लू गंभीर रेस्पिरेटरी लक्षण और स्थितियों का कारण भी बन सकता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:-

न्यूमोनिया
रेस्पिरेटरी फेलियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
सांस की तकलीफ डिस्पेनिया

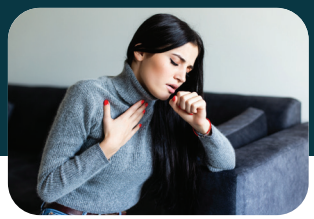

किसे प्रभावित करता है बर्ड फ्लू?

बर्ड फ्लू आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है, जो जीवित या मृत संक्रमित पक्षियों के साथ संपर्क में रहे हैं। इनमें मुर्गियां, टर्की, जलपक्षी (बतख, हंस) और शिकार करने वाले पक्षी (बाज) शामिल हो सकते हैं, जो जंगल में संक्रमित जलपक्षी के संपर्क में आए हों। संक्रमित पक्षी अपनी लार, मल (मल) और बलगम के जरिए वायरस फैला सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ मामलों में, संक्रमित पक्षियों के संपर्क से संक्रमित होने वाले इन लोगों में उनके परिवार के सदस्य और अन्य करीबी संपर्क भी संक्रमित हो सकते हैं।

बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद जिन लोगों में गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा सबसे अधिक होता है उनमें निम्न शामिल हैं-

गर्भवती महिलाएं
कमजोर इम्युनिटी वाले लोग
65 साल या उससे अधिक उम्र लोग

बर्ड फ्लू कैसे फैलता है?

अगर आप ड्रॉपलेट्स या धूल में मौजूद वायरस में सांस लेते हैं, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। किसी संक्रमित चीज को छूने के बाद उसी हाथ से फिर अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं।

इसके अलावा बर्ड फ्लू उन लोगों से भी फैल सकता है जो संक्रमित थे, जिनका संक्रमित पक्षियों से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन यह दुर्लभ है। आपको ठीक से प्रोसेस्ड मुर्गे आदि को खाने से बर्ड फ्लू नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ऐसी कोई भी चीज खाने से बचना चाहिए जिसमें कच्चा मांस या खून शामिल हों।

बर्ड फ्लू से बचाव कैसे करें

बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है, जो मुर्गीपालन का काम करते हैं। अगर आप पोल्ट्री में काम करते हैं, तो आपको हर समय सुरक्षात्मक उपकरण पहनने जैसी सावधानियां बरतना जरूरी है। अगर आप पोल्ट्री में काम नहीं करते हैं, तो यात्रा करते समय पोल्ट्री फार्मों और बाजारों जाने से बचें। अगर आप जंगली बत्तखों या अन्य जलपक्षियों के संपर्क में हैं, तो सावधान रहें। हमेशा हाथ धोने की आदत को अपनाएं और गंदे हाथों से अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, जहां बर्ड फ्लू के मामले हैं, तो सुनिश्चित करें कि अगर आपमें फ्लू के कोई लक्षण हों, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

साजिद अली
विशेष संवाददाता

पाकिस्तान में 'शरीफ़' सरकार

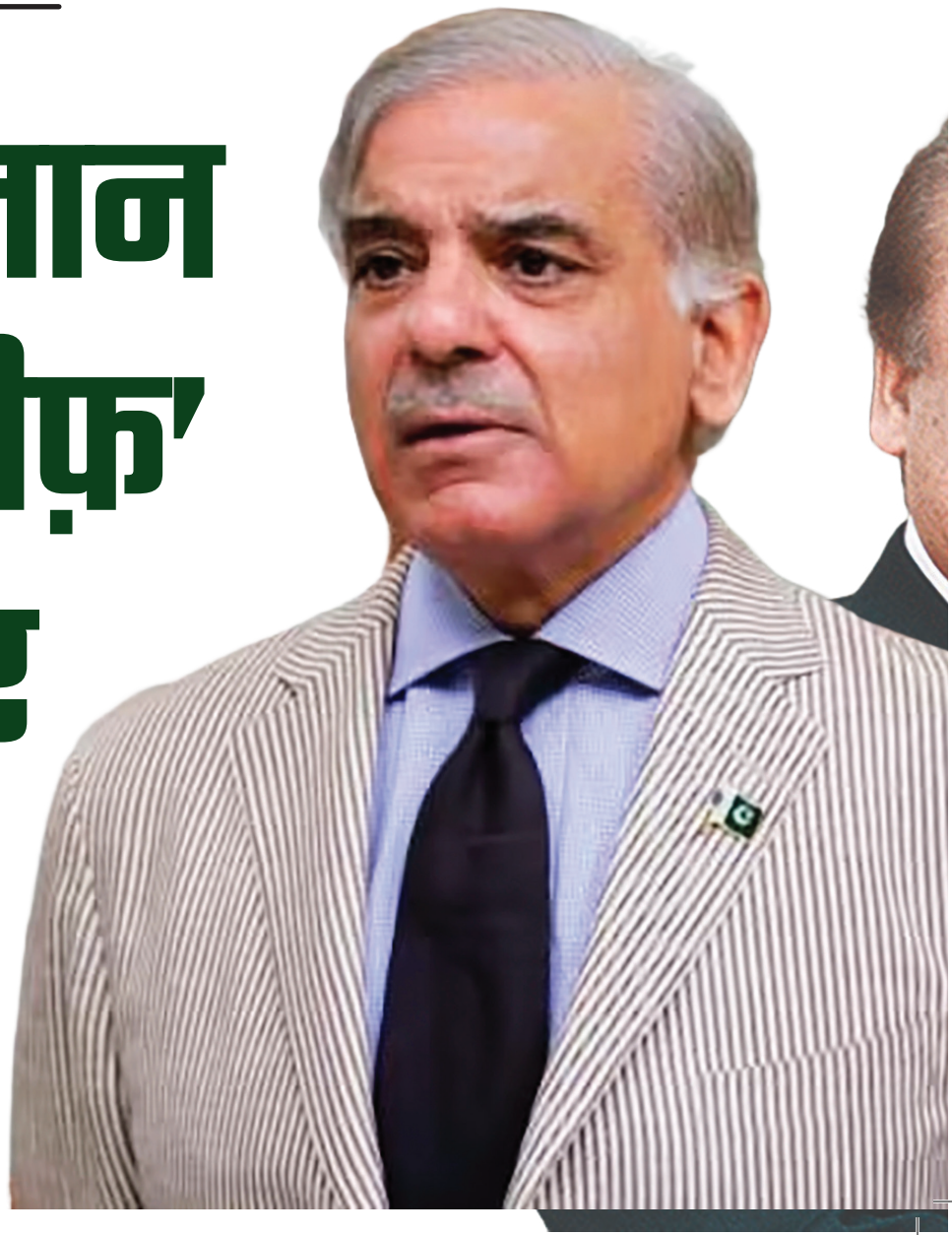

पाकिस्तान में नई सरकार के जल्द गठन की उम्मीद जग गई है। पीएमएल-एन ने बुधवार को शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से नामित कर दिया। वह गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही पीएमएल-एन के वरिष्ठ नेता सरदार अयाज सादिक को नेशनल असेंबली के स्पीकर पद के लिए नामित किया है। सरकार बनाने को लेकर यह प्रगति नेशनल असेंबली के उद्घाटन सत्र से एक दिन पहले हुई है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) संसदीय दल की बैठक इस्लामाबाद में बुधवार को पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नवाज ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए व वफादार सरदार सादिक को स्पीकर पद के लिए नामित किया। यह जानकारी पीएमएल-एन के सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी अतातुल्ला तरार ने दी। नवाज ने कहा कि नई सरकार की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। शहबाज के सामने पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों को सही करने के साथ-साथ गिरती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की चुनौती होगी।

नेशनल असेंबली की आरक्षित सीटों का आवंटन

राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा सत्र बुलाने से इनकार करने के बाद नेशनल असेंबली के निवर्तमान स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने गुरुवार को सत्र आहूत किया है। पीएमएलन-एन व पीपीपी के नेताओं ने

चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाने से इनकार करने से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। अल्वी ने सोमवार को सत्र बुलाने से यह कह कर इनकार कर दिया था कि सत्र बुलाने से पहले नेशनल असेंबली की आरक्षित सीटों का आवंटन होना जरूरी है। अल्वी इमरान खान की पार्टी पीटीआइ से जुड़े रहे हैं।

तीन पार्टियों ने चुनाव नतीजों को किया खारिज

पाकिस्तान में नई सरकार बनाने की कवायद के बीच चुनाव में धांधली का शोर थमता नजर नहीं आ रहा है। तीन विपक्षी पार्टियों ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए), जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआइ-एफ) और जमात-ए-इस्लामी (जेआइ) ने मंगलवार को चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया। तीनों पार्टियों ने आठ फरवरी को हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते फिर से चुनाव कराने की मांग की है। तीनों पार्टियों ने कहा है कि वे चुप नहीं बैठेंगी, वे धांधली के विरुद्ध आवाज बुलंद करती रहेंगी।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी ने एलान किया है कि वह चुनाव में धांधली के विरुद्ध दो मार्च को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस बीच, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान ने इंटरनेट मीडिया में दो आडियो क्लिप प्रसारित कर दावा किया है कि ये चुनाव में धांधली के आरोपों की पुष्टि करते हैं। वहीं, इस्लामाबाद में कुछ पत्रकारों ने प्रदर्शन कर पत्रकार असद अली तूर पर दर्ज एफआइआर वापस लेने की मांग की।

इमरान का क्या होगा?

पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव की सरगर्मियों के केंद्र में इमरान खान थे। उनके लिए यह चुनाव उठापटक वाले साबित हुए। चुनाव के पहले के हालात साल 2018 जैसे ही थे। पाकिस्तान में हमेशा किंगमेकर के रोल में रहने वाली आर्मी के सामने इस बार इमरान खान खड़े थे। चुनाव से पहले उनकी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया गया। इमरान जेल में हैं और अगले 14 साल तक उनके जेल में रहने की आशंका है। इसके बावजूद उनकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी से ज्यादा वोट मिले। आखिर यह संभव कैसे हुआ?

सीधा किया संवादः इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास चुनाव चिह्न नहीं था। मगर, पार्टी ने सोशल मीडिया और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया। इमरान खान तीनों पार्टियों में एकमात्र ऐसे लीडर रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया के हर पॉपुलर प्लैटफॉर्म पर पर्सनल अकाउंट है। इसी के जरिए उन्होंने वोटर्स से सीधा संवाद किया।

आर-पार के मूड मेंः चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच ये जाहिर है कि इमरान भले ही सरकार बनाने की हालत में न हों, लेकिन उनके हाल फिलहाल के कदमों को देखकर लगता है कि वह सेना के साथ आर-पार के मूड में हैं। एक ओर इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड (IMF) को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान को नया लोन देने से पहले इलेक्शन ऑडिट करवाने को कह रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इमरान की पार्टी के अध्यक्ष गौहर अली खान को हटा दिया गया है। मार्च में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इमरान जानते हैं कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की ये उनकी आखिरी जंग है। हालांकि, उनकी दिक्कतें आसान होती नहीं दिख रही। उन पर कई केस हैं। यह साफ है कि 71 साल की उम्र में वह अपने राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं।

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

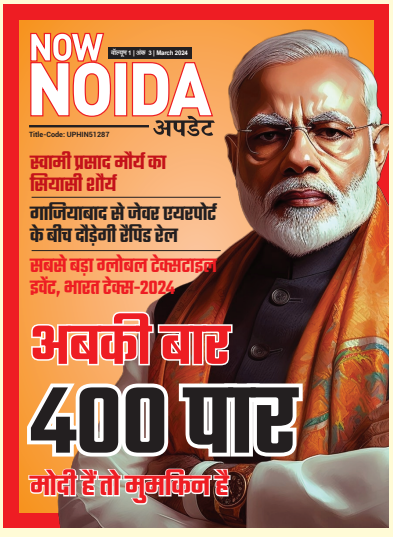

पत्रिका सदस्यता प्रपत्र

भारत के व्यक्तियों के लिए वार्षिक सदस्यता: ₹440 ☐

भारत के बाहर और कॉर्पोरेट दरें: ₹2,000 ☐

Name .....

Address.....

.....

.....

.....

Postcode.....

Telephone.....

Email.....

कृपया चेक या पोस्टल ऑर्डर करें

MBI Digital Private Limited को देय।

MBI
Made By India
DIRECT FROM FACTORY

Organic Cotton Muslin Baby Swaddle clothes

HIGH-QUALITY BAMBOO T-SHIRTS

Direct from Factory

SHOP AT

www.madebyindia.com

Plot no. 99, Ecotech-3, Greater Noida | sales@madebyindia.com | 07011412854